पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

www.geocities.com\samayamaya\march08.pdf

पंजीयन क्रमांक RNI NO. MPHIN\2006/20685

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार

B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569

Phone Fax : 91-731-2530859

Websites : www.samaymaya.info

www.geocities.com/corruption2india/eduIndore.html

www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html

www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html

www.geocities.com\samayamaya\feb08.pdf

E-mail : mwc@indiatimes.com

: linkdage@hotmail.com,

(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

In case of any disputes, all distputes can be sue only in Indore Court.

वर्ष 1 अंक 30 इंदौर, सोमवार 17 से 23 मार्च 2008 तक पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 ✦ लोकतंत्र का नाटक २-३ वर्ष

3 ✦शासन की हठधर्मी से दुःखी हैंडपंप टेक्निशियन

4 ✦कां.यं.राणे, मु.अ. अग्रवाल आंख मींच कर रहे भुगतान

5 ✦150 शेर भी नहीं है प्रदेश में

7 ✦भ्रष्टाचार, मूल कारण है अपराधों में लगातार वृद्धि

8 ✦प्रेसकर्मी और पत्रकार भी हैं शोषण के शिकार

पूंजीपतियों की आवश्यकता और इशारे पर बजट

लालू रेलवे को बिहार की तरह कबाड़ बना देगा

केंद्र व राज्य बजट वोट लुभावन लालू रेल बजट

- **आंकडों की बाजीगरी, महंगाई बढ़े**
- **उपभोक्ता की भोग संस्कृति बढ़े और पूंतीपतियों की कमाई हो**
- **कारें व अन्य उपभोक्ता सामग्री सस्ती अधिकतम मध्यमवर्गीय को फंसाने का षड्यंत्र**

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के बजट में कारें व पूंजीगत सामग्री सस्ती की गई। जो पूंजीपतियों व बड़े उद्योगपतियों, टाटा, बिरला एवं

किसानों को लुभाने और वोट कबाड़ने की रणनीति के तहत ही बनाया गया, इसके विपरीत दोनों ही आम उपभोक्ता वस्तुओं पर करों की दरों में कमी या

पर भी चुप्पी साध रखी है। जिसे आम उपभोक्ता से लूटा जा रहा है।

शिक्षा के नाम पर दोनों ने ने ही

भारतीय रेलवे के इतिहास में 5वीं बार लाभ दिखाकर किराया घटाकर, वोट के लिए जनता को रियायते देकर भले ही विश्व के इस विशाल शासकीय संस्थान और अपना स्वयं का नाम विश्व गिनीज बुक में लालू ने दर्ज करवा लिया हो इसके विपरीत सच्चाई यह भी है कि रखरखाव और अवक्षयण (डेप्रीशियशन) अगर चिट्ठे में नहीं दिखाई जाएगी या वास्तविकता में इस विशाल यांत्रिकीय संस्थान में रखरखाव खर्च जो स्तर के मान से आवश्यक है जैसे कि रेलवे पटरी पर हर तीन माह में

चुनाव के बाद ललुआ को रेलमंत्री नहीं बनना

रुपए २५००० करोड़ का लाभ केवल कागजी

का हो रहा है। अर्थात् आवश्यक

का ये इंजीनियरिंग संस्थान आवश्यक रखरखाव के अभाव में कबाड़ में बदल जाएगा। जब जनता सरकार और राज्य की सरकारों को समझ में आएगा जब आए दिन दुर्घटनाएं होंगी और सैकड़ों लोग इन हादसों में मारे जाएंगे।

बेशक इस गहरी लंबी चाल का उद्देश्य रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि जो अभी रुपए 25000 करोड़ लाभ को

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के बजट में कारें व पूंजीगत सामग्री सस्ती की गई। जो पूंजीपतियों व बड़े उद्योगपतियों, टाटा, बिरला एवं विदेशी कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। यदि सस्ती नहीं होगी तो मध्यमवर्गीय लोगों की पहुंच से दूर होंगी तो खरीदेगा कौन, क्या फैक्ट्रीयां चौपट करवाएगी सरकार जिससे उसके मंत्रियों, संत्रियों को मोटा कमीशन मिल रहा है। दूसरी श्रेणी में आम मध्यवर्गीय उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए आयकर की सीमा 1.10 से बढ़ाकर 15 लाख की गई, ताकि कारों के साथ जो और सस्ते किए गए उनमें दुपहिया, तिपहिया वाहन, फ्रिज, दो टन से बड़े एसी, एड्स जीवन रक्षक दवाएं, कागज, पेपर बोर्ड, जवाहरात, डेयरी उत्पाद, स्टील मेल्टिंग स्क्रैप, पशु और कुक्कुट खाद्य, फास्फोरिक एसिड, सेट टॉप बाक्स, शिशु सदन सुविधाएं, कम्पोस्टिंग मशीनें, वायरलेस डाटा कार्ड, पैक नारियल पानी, चाय, काफी, मिश्रण, मुरमुरे, जल शुद्धिकरण यंत्र, फ्लश दरवाजे, नाश्ते के अन्न, जीवाणुविहीन प्रसाधन, गद्दियां, पैकेजिंग सामग्री, खिलाड़ी कर्मचारी का प्रायोजन, खेलकूद का आयोजन, अतिथि गृहों को लाभ कर एफबीटी से बाहर।

अर्थात पूंजीपतियोंको तो पूर्णतया खुश किया और जनता की खुशी का बहाना देकर आम उपभोक्ता की दैनिक उपयोग की वस्तुएं जिसमें खाद्य तेल ही 25-50 प्रतिशत तक उछल गया, खाद्यान्न गेहूं, दाल, शक्कर आदि सब महंगे कर दिए गए जो सीधे ही जनता के पेट पर लात लगाकर भूखे सोने के लिए मजबूर करने लगे हैं।

म.प्र. सरकार और केंद्र सरकार दोनों का बजट सच मायने में मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय और किसानों को लुभाने और वोट कबाड़ने की रणनीति के तहत ही बनाया गया, इसके विपरीत दोनों ही आम उपभोक्ता वस्तुओं पर करों की दरों में कमी या नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। आंकडों की बाजीगरी कर, दोनों ने ही किसानों को लुभा कर ग्रामीण वोट बटोरने के शिगूफे ही छोड़े हैं।

जहां म.प्र. सरकार ने बिजली बिलों में की गई जालसाजियों से राहत दी है, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को राहत की तो दूर उसमें विवेकीकरण भी नहीं किया। साथ ही जो दिग्गी दानव की सरकार ने इलेक्ट्रानिक मीटर लगाकर 25 से 40 प्रतिशत की ज्यादा वसूली की जा रही है उस पर भी चुप्पी साध रखी है। जिसे आम उपभोक्ता से लूटा जा रहा है।

शिक्षा के नाम पर दोनों ने ने ही शिगूफे छोड़े हैं। आम मध्यमवर्गीय, निम्न या मध्यमवर्गीय सरकारी स्कूलों में नहीं जाते हैं। उनके बच्चों को पढ़ाई का खर्च तो उन्हें पूर्व की तरह उठाना ही पड़ेगा। दोनों ही सरकारों ने किसानों के हित में जो दांव खेले हैं। उनका मूल उद्देश्य शुद्धतः वोट के वर्ष को सफल चुनाव वर्ष के रूप में अपनी सरकार स्थापित करने का प्रयास है जो भविष्य निर्धारित करेगा।

दोनों ही सरकारों ने अपने

शेष पेज २ पर

अमेरिका क्यों उतावला है परमाणु समझौते के लिए

बुश बटोरने में लगा अपने अंतिम चरण में

भारत में अमेरिकी राजदूत मलफोर्ड, परमाणु समझौते के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना रहा है, जिसमें न केवल भारतीय और अमेरिकी मीडिया वरन अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिकी प्रशासन, भारत सरकार को चला रहे पक्ष और विपक्ष के दलों पर दबाव बनाने का अथक प्रयास कर रहा है।

आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति बुश, प्रशासन और भारत में अमेरिका राजदूत मलफोर्ड परमाणु समझौते के लिए जो हथकंडे अपना रहे हैं वो सिद्ध करता है कि न केवल अमेरिकी सरकार के इरादे कहीं से न तो नेक है न ही सदभावनापूर्ण, भारतीय हितों को गिरवी करने की तैयारी है। यहां इस उतावलेपन से स्पष्ट होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बुश, उनके मंत्री, भारत में अमेरिकी राजदूत, सबका परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने वाली कंपनियों से उन्हें भारी कमीशन प्राप्त होगा, जिसे भारत से ही वसूला जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति बुश का कार्यकाल सितम्बर 08 से समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस समझौते की अंतिम तारीख को सितम्बर 08 तक बढ़ा दिया गया है। इससे कमीशनखोरी का सच प्रगट होता है।

बेशक इस कमीशन में सोनिया, मनमोहन के अतिरिक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे सचिवों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा सचिवों का भी मोटा कमीशन है, इसलिए सब पक्ष में बैठे कम्युनिस्टों को राजी करने के साथ ही विपक्ष की भी सहमति बनाने के लिए न केवल स्वयं, वरन् अमेरिकी राजदूत और अन्य तरीकों के साथ मीडिया में आम जनता के दिमाग में परमाणु समझौते के पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर हथकंडे का प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि कांग्रेस

शेष पेज २ पर

जाएगी या वास्तविकता में इस विशाल यांत्रिकीय संस्थान में रखरखाव खर्च जो स्तर के मान से आवश्यक है जैसे कि रेलवे पटरी पर हर तीन माह में गिट्टी डाली जानी चाहिए, अगर दो वर्ष में भी एक बार भी नहीं डाली जा रही है। जिससे हजारों टन की रेल पटरी पर तरीके से दौड़ सके। उस पर घास न उगे, स्लीपरों की पकड़ जमीन पर बनी रहे, जिससे पटरियों को संतुलित किया जा रहा है, अगर नहीं डाली जा रही है तो स्वाभाविक है पटरियों का संतुलन बिगडेगा और रेल पटरियों से उतरेगी जैसा कि आए दिन हर डिवीजन में दो-चार जगह पटरियों से ट्रेनें उतर रही हैं। यह हाल पूरे देश की रेलवे

का हो रहा है। अर्थात् आवश्यक रखरखाव भी नहीं किया जा रहा है तो जो खर्च बच रहा है उससे अभी भले ही रुपए 25000 करोड़ का लाभ दिखा दिया जाए, पर आने वाला कल क्या होगा, जनता, यात्री और इंजीनियरिंग विशेषज्ञ इस तथ्य को समझ सकते हैं कि आने वाले कल में जैसे लालू ने बिहार में 15 वर्ष राज्य करके उसे पूरे कबाड़ में बदल दिया था वैसे ही इसके 5 वर्ष के मंत्री पद पर पूरा विश्व का ये विशाल रेलवे अगले 50 वर्ष भुगतेगा। इसके जाते-जाते रेलवे

बेशक इस गहरी लंबी चाल का उद्देश्य रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि जो अभी रुपए 25000 करोड़ लाभ को फिर से बचाने के लिए रुपए 5 लाख करोड़ की आवश्यक होगी, क्योंकि फिर तत्काल में एक लाख कि.मी. से ज्यादा की न केवल पटरियों को वरन पूरे ट्रेक को चलायमान रखने के लिए रुपए 1 लाख करोड़ की आवश्यकता भी होगी, ताकि पुनः भराव करके नए स्लीपर डालकर पटरियों पर ट्रेनें दौड़ा सकें।

लालू के 5 वर्षों बाद रेलवे के इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि बिहार का जानवरों का करोड़ों का चारा चरने वाला देश के विशालतम इंजीनियरिंग संस्थान का मंत्री बना तो पूरे रेलवे को 5 वर्ष में इतना चर गया कि आने वाले 50 वर्षों में भी उसके निशान साफ नहीं हो सके, उसके 5 वर्षों के मंत्रीकाल के उपरांत रेल मंत्री रेलवे में होती रोज की ट्रेन दुर्घटनाओं में मरने वालों की लाशें देखकर स्वयं जिंदा लाश बन जाएगा।

दुनिया के प्रबंधन गुरुओं का महागुरु बनने वाला यह धूर्त सचमुच अगर टाटा जैसे संस्थानों का प्रबंधक बन जाए तो दुनिया में तो क्या देश में अगले 10 वर्ष के बाद टाटा का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा।

मृत ओसामा की आड़ में

कब तक तांडव करेगा? आतंकी अमेरिका

विश्व के आतंकी अमेरिका ने अपने आतंकी मुखोटों के लिए जिस ओसामा बिन लादेन को अभी तक उपयोग किया, वास्तव में वह अगस्त-सितम्बर 06 के अंत में ही मृत्यु हो चुकी थी। जिसके संबंध में फ्रांसीसी अखबारों ने उसकी लीवर कैंसर से मृत्यु की घोषणा कर दी थी इसके विपरीत अमेरिका उस ओसामा के भूत का अभी तक अपने परम धूर्तता पूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहा है, ताकि उसे दक्षिण एशिया के इस महत्वपूर्ण अड्डे अफगानिस्तान से न हटना पड़े।

अफगानिस्तान में पैर जमाने के लिए 1970 के दशक से ही अमेरिका ने रूसी फौजों को हड़काने और हटाने के लिए अपनी गोटियां जमाना शुरू कर दी थी। इसके लिए उसने पाकिस्तान का उपयोग उसकी आजादी के बाद

शेष पेज २ पर

साप्ताहिक
समय माया

सम्पादकीय

वोटों का बजट, आंकड़ों की चासनी, जेब पर डाका

केंद्र सरकार ने आगामी चुनावों के मद्देनजर जनता को आंकडों की जो चासनी चटाई है। सच वो चासनी की मिठास का असर दो दिन में ही दिखने लगा है, जो छूटे, उसे दे दी गई है, आयकर में उसका लाभ वेतन भोगीयों को ही मिलेगा अवश्य, इसके विपरीत उस पर उपभोक्ता वस्तुएं जो वास्तविकता में उसे प्रतिदिन उसके जीवन यापन में उपयोगी है उनकी सबकी कीमतें पिछले दस दिन में 10 से 25% तक बढ़ गई है।

पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के उत्पादित माल को बाजार में खपाने और बिक्री बढ़ाने के लिए उसने वाहनों, एसी, जवाहरात, स्टील, स्क्रेप, सेट टॉप बाक्स, कंपोस्टिंग मशीनें, वायरलेस, डाटा कार्ड, जलशुद्धिकरण यंत्र जैसी वस्तुओं की कीमतें कम की हैं। ये वस्तुएं एक बार वर्ष दो चार वर्ष में एक बार खरीदी जाती है। साथ ही इन वस्तुओं में उपोयग आने वाला पेट्रोल-डीजल की कीमतें उसने पहले ही बढ़ाकर जनता की जेब पर डाका डाल दिया था। बिजली की खपत बढ़ाएंगे जबकि विद्युत की कमी से पहले ही राष्ट्र पीड़ित हो रहा है, पिछले 10-20 वर्ष से इनकी खरीदी हो पूंजीपतियों की जेबों में आम मध्यमवर्गीय से लेकर निम्न मध्यमवर्गीय तक इसका उपयोग करने लायक बन सके अवश्य ध्यान रखा गया।

कृषक वर्ग को केंद्र व राज्य ने दोनों ने राहत अवश्य दी है पर उसमें भी लघु एवं सीमांत कृषक वंचित ही रहेगा। जिसके उन्हें वोट कबाड़ने थे शायद वो सहारा नहीं प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि वह तो पूर्व से ही साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ उसको आम उपभोग की वस्तुएं यथा गेहूं, चावल, दालें, तेल व अन्य खाद्यान्न, शक्कर, मिट्टी का तेल सबके महंगे होने से तो हाल फिलहाल मध्यमवर्गीय से लेकर अतिगरीबों तक की जेबों पर डाका ही डाला गया है।

आखिर आंकडों की चासनी की मिठास दिमागी मिठास तो दे सकती है पर पेट को तो दो वक्त के भोजन की आवश्यकता होती है, यदि दो वक्त का भोजन पहुंच से दूर हो रहा है तो आंकडों की चासनी से दिमाग को भी कितनी देर मिठास मिल सकेगी, मात्र चंद सेकंड?

आम उपभोक्ता वस्तुएं यदि बजट के आते ही महंगी होने लगी है जो रोजमर्रा के काम आती है तो आने वाले चुनावों में सरकार के स्थायीकरण की उम्मीद तो निरर्थक ही हो जाएगी।

वोटों के लिए आंकडों की बाजीगरी से शब्दों का मायाजाल बिखैर कर कब तक जनता को भ्रमित किया जा सकेगा। इसका यथार्थ तो चंद दिनों में ही सामने आने लगा है। आम जनता के लिए तो आवश्यक था पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर से करों का बोझ कम किया जाता, खाद्य

पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाली का दिवास्वप्न

लोकतंत्र का नाटक २-३ वर्ष

पाकिस्तान के नवाज शरीफ और जरदारी पार्टी जीत तो अवश्य गई है, परंतु कोई भी प्रधानमंत्री की घोषणा नहीं कर रहे हैं। अधिकांश प्रधानमंत्रीयों का इतिहास गवाह है कि क्या हश्र हुआ है, उनका पाकिस्तान में अमेरिका की जैसी छवि पाकिस्तान व पूरे विश्व में उसके मुशर्रफ की सरकार को पालने और संरक्षण देने के कारण बन गई है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली उस आतंकवादी छवि को सुधारने में मददगार सिद्ध होगी।

पिछले 60 वर्षों से पाकिस्तान में 40 से ज्यादा वर्ष वहां सैनिक शासनरहा है, भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो के तख्ते पलटे गए, उन्हें निर्वासन की जिंदगी झेलना पड़ी। बाद में चुनावों के दौरान बेनजीर की हत्या करवा दी गई।

अमेरिकी प्रशासन के लिए दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पाकिस्तान और उसकी सेना से अच्छा पिछले 60 वर्षों में कोई मोहरा नहीं मिला पाकिस्तान में लोकतंत्र के आ जाने से अमेरिकी प्रशासन को दक्षिण एशिया में अपने कार्यों को अंजाम देने, चीन, भारत, रूस में आतंकी गतिविधियां चलाने, अपना व्यावसायिक कचरा फेंकने-बेंचने, हथियार बेचने आदि के लिए जो पाकिस्तानी सैन्य प्रशासन का उपयोग कर तरीके से अंजाम दे पाता है वह कार्य वो पाकिस्तान में लोकतंत्र के रहते मुश्किल से कर पाता है। उसकी इस आतंकवादी छवि का न केवल पाकिस्तान में पिछले कई वर्षों से विरोध हो रहा था वरन उसकी इन सच्चाइयों का खुलासा पूरे विश्व में भी हो रहा था। इसलिए अमेरिकी प्रशासन को वहां लोकतंत्र की बहाली आवश्यकता बन गई थी, ताकि अमेरिका अपनी गुंडागर्दी की, आतंकवादी छवि को पाकिस्तानी और विश्व की जनता के मस्तिष्क से धुंधला कर दे, तो पुनः दानी, धर्मी खैरात बांटने वाला आका बन सके। अब जबकि पाकिस्तान में चुनाव हो चुके हैं सरकार बनाने की जद्दोजहद चल रही है, समस्या प्रधानमंत्री बनने की है। वास्तविकता में प्रधानमंत्री बनने की नहीं वरन् अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तानी सेना के तख्तापलट पर बलि का बकरा बनने की है कि आखिर कौन अगला प्रधानमंत्री पद की बलि का बकरा बनेगा। इतना तो पक्का है पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाली का ये नाटक 2-3 वर्ष से ज्यादा तो नहीं चलेगा या चलने दिया जाएगा। अमेरिका प्रशासन पाकिस्तान में लोकतंत्र का नाटक जितना लंबा खेलेगा उसकी उतनी ही दक्षिण एशिया में पकड़ कमजोर होगी। उसकी पकड़ कमजोर होने का मतलब है सीधे-सीधे रुस, चीन और भारत उसकी गिरफ्त और चालबाजियां दिखाने, कारगुजारियां करने में असहयोग जो कि उसकी बहुराष्ट्रीय, व्यावसायिक, सामरिक कंपनियों और पूंजीपतियों के व्यासायिक हितों को नुकसान पहुंचाएगा।

इसलिए अमेरिका इस नाटक को संभवतः अधिकतम 3 वर्ष ही चलने देगा। मुशर्रफ रहें न रहें सैन्य प्रशासक के रूप में वरन दूसरे सेनाध्यक्षों के माध्यम से इस लोकतंत्र का वह फिर 10-5 वर्ष के लिए तख्ता पलटवाएगा ही। अमेरिका को पाकिस्तान में सैन्य प्रशासन उसकी दक्षिण एशिया में यशमेन की भूमिका का निर्वहन करता है। उसे अपने हित साधनें में पाकिस्तानी सैन्य प्रसासन के यशमैनों ने ही सोवियत रूस में अफगानी सीमा में अपने ओसामाओं जो तालिबानी हिजबुली, लश्करे तैयबा के माध्यम से रूस को 26 टुकड़ों में बांटा, अफगानिस्तान पर कब्जा कर दक्षिण एशिया में आतंक का तांडव फैलाया। भारत के उत्तरीक्षेत्रों में कृत्रिम बाढ़ भरे जून की गर्मी को तपिश में, जिससे हिमाचल प्रदेश व पंजाब झुलसे, कृत्रिम भूकंप जिसमें काश्मीर व पाकिस्तान में बर्बादी हुई, अब अमेरिका अपने अफगानी अड्डे से भारत, रूस, चीन, ईरान पर नजर रखता है।

बुश बटोरने में लगा...

शेष पेज १ का

परमाणु समझौते के बहाने बुश स्वयं भी कमीशन चाहता है

का पुराना इतिहास रहा है।

अमेरिकी बुश कम से कम दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्रों को अपने पाले हुए श्वानों से ज्यादा कोई तवज्जों नहीं देते न ही उनकी निगाहों में इनकी कोई अहमियत है।

इस राष्ट्र का, राष्ट्र की 120 करोड़ जनता का कितना बड़ा दुर्भाग्य

कुछ प्रकाशित कर दिया है। साथ ही हमारे अपने राष्ट्र में जो थोरियम, यूरेनियम के आकूत भंडारों के दोहन से परमाणु ईंधन की आसान प्राप्ति सुनिश्चित कर अगले 20 वर्षों तक परमाणु भट्टियों के ईंधन की व्यवस्था की जा सकती है। पर जब सवाल आयातक राष्ट्र के सत्ताधीशों को प्राप्त

का षड्यंत्र समाप्त होने के साथ ही बुश, उसके प्रशासनिक सचिवों भारत में अमेरिकी राजदूत को मिलने वाली दलाली का ख्वाब भी न केवल ठंडा हो जाएगा। वरन भारत के सत्ताधीशों मनमोहन, सोनिया व अन्य के साथ ही सचिवों को भी

केंद्र व राज्य बजट

शेष पेज १ का

शासकीय कर्मचारियों को भी खुश करने का भरपूर प्रयास किया है, ताकि वो पुनः उन्हीं की सरकारें स्थापित करने में अहं भूमिका का निर्वहन करें। आंख भींचकर इनके पक्ष में वोटिंग करवाएं।

म.प्र. में शिव की सरकार कर्मचारियों पर अधिकतम मेहरबान है बेशक इससे म.प्र. के सरकारी

की उम्मीद तो निरर्थक ही हो जाएगी।

वोटों के लिए आंकडों की बाजीगरी से शब्दों का मायाजाल बिखैर कर कब तक जनता को भ्रमित किया जा सकेगा। इसका यथार्थ तो चंद दिनों में ही सामने आने लगा है। आम जनता के लिए तो आवश्यक था पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर से करों का बोझ कम किया जाता, खाद्य तेलों के आयात पर से ड्यूटी कम की जाती। मिट्टी का तेल राशन दुकानों पर भले ही रुपए 10 के भाव बेचा जा रहा हो पर सकी वितरण प्रणाली में हो रहे भ्रष्टाचार से वह रुपए 30 प्रति लीटर बिक रहा है, जो आम, निम्न, मध्यमवर्गीय गरीबों के लिए भारी कष्टप्रद हो रहा है।

यह कटु सत्य है कि वित्तमंत्री राज्यों का हो या केंद्र का वह उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की कठपुतली होता है। उनके इशारों पर नृत्य करता है। स्वाभाविक है उनके हितों में ही आंकडे बढ़ाए, घटाए जाएंगे, ताकि वो बाद में वित्तमंत्री व उनकी सरकार का ख्याल रखें। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है।

हुए श्वानों से ज्यादा कोई तवज्जो नहीं देते न ही उनकी निगाहों में इनकी कोई अहमियत है।

इस राष्ट्र का, राष्ट्र की 120 करोड़ जनता का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके शासक जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं राष्ट्र के हितों को अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के खातिर गिरवी करने में आगे बढ़कर बलि चढ़ाते हैं। परमाणु समझौता 123 के माध्यम से खरीदा जाने वाला ईंधन की आड़ में जो कुत्सित साजिश रची गई है उसके बारे में पूर्व में भी 'समय माया' ने काफी

से परमाणु ईंधन की आसान प्राप्ति सुनिश्चित कर अगले 20 वर्षों तक परमाणु भट्टियों के ईंधन की व्यवस्था की जा सकती है। पर जब सवाल आयातक राष्ट्र के सत्ताधीशों को प्राप्त होने वाले मोटेकमीशन का हो तो सारे स्पष्टीकरण गौण और निरर्थक हो जाते हैं। आखिर अमेरिकी उतावलेपन, षड्यंत्र, जालसाजी से भी अगर हम सीख लेंगे तो भी हमारा सौभाग्य होगा। बुश की सत्ता चंद महीनों की ओर है। अमेरिका में बुश की सत्ता जाते ही परमाणु आपूर्तिकर्ताओं अमेरिकी कंपनियों

दलाली का ख्वाब भी न केवल ठंडा हो जाएगा। वरन भारत के सत्ताधीशों मनमोहन, सोनिया व अन्य के साथ ही सचिवों को भी कमीशन से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए पुनः इस समझौते को सितम्बर 09 तक इसलिए ही बढ़ाया गया है कि हो सकता है वर्तमान भारत सरकार में बैठे सोनिया, मनमोहन भारतीय संसद में बैठे पक्ष और विपक्ष के सांसदों को मनाने में सफल हो जाएं। जाते-जाते कुछ करोड़ अमेरिका डॉलर बुश एंड कं. बटोर सके।

वोटिंग करवाएं।

म.प्र. में शिव की सरकार कर्मचारियों पर अधिकतम मेहरबान है बेशक इससे म.प्र. के सरकारी कर्मचारी भारी लाभान्वित तो हुए हैं। परंतु जितना मिलता है उतना ही कम, इसलिए संतुष्टी कभी पूरी नहीं होती, चाहे वो धैले का भी काम नहीं करें।

हमारे देश में केंद्र सरकार जो बजट बनाती है वो जनता को ध्यान में रखकर नहीं वरन पूंजीपतियों की आवश्यकताओं को और उनके इशारे पर जो उन्हें आने वाले काल में अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए जनता को आसानी से पूंजीपति निचोड़ सकें। उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की कमाई, आय के स्त्रोत बढ़ सकें, के हितों को ध्यान में रखकर ही वित्तमंत्री बजट बनाता है।

अब जबकि चुनाव आने वाले हैं तो चंदा कौन देगा? एक मुश्त, उद्योगपतियों और पूंजीपति ही देंगे, तो स्वाभाविक है, वित्तमंत्री चिदंबरम उनके इशारों पर पूंजीपतियों का हितकारी बजट जनता को कल्याण की तेज रोशनी की चकाचौंध में धीरे से लूटने वसूलने की प्रक्रिया वाला ही बनाया जाता है या जोर का झटका धीरे-धीरे लगाया जाता है। पूंजीपतियों की थैलियां धीरे-धीरे भरती रहे। सत्ताधीश एक मुश्त चुनावी चंदे के नाम अरबों रुपए उनसे वसूल सकें। इसलिए चंदा संस्कृति विकास के लिए महंगी उपभोक्ता वस्तुओं पर से कीमतें घटाई गई। कारों, दुपहिया, तिपाहियां वाहनों की कीमतें तो कम कर दी गई थी पर उसके पहले ही उसमें लगने वाले पेट्रोल-डीजल की कीमतें जरूर बढ़ा दी गई थी जो सारे कम किए करों की कीमत से कई गुना ज्यादा कीमतें वसूल लेगा।

कब तक तांडव...

शेष पेज १ का

डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय हो गया ओसामा की मौत को

से ही शुरू कर दिया था। 70-80 के दशक में पहुंचकर ओसामा को खड़ा किया, फिर तालीबानी फौजों, लड़ाकों इकट्ठा कर अफगानिस्तान से रूसी फौजों को खदैड़कर धीरे-धीरे 1980-1985 के बीच रुस में घुसपैठ कर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति सम्पन्न राष्ट्र को सोवियत रूस से 26 टुकड़ों में बांट कर 26 राष्ट्रों को खड़ा कर दिया ताकि वो पुनः शक्ति सम्पन्न न हो, उसे न केवल टक्कर न दे सके, वरन उसकी बराबरी में खड़ा रहकर उस गुंडे से आंख भी न मिला सके, इन सब कार्यों में अमेरिकी पिट्ठू ओसामा का उसने खुलकर उपयोग किया।

अब इन सारे तथ्यों को देखकर विश्व की ये जनता को ये विश्वास करने के पर्याप्त कारण समझ आएंगे कि अमेरिका के वर्ल्डट्रेड सेंटर पर आतंकियों का नहीं वरन स्वयं अमेरिकी ही चाल का परिणाम था उसको उड़ाना, उससे अमेरिकी प्रशासन ने एक साथ कई निशान साधे, जैसा कि फ्रांस ने सच्चाइयों को बयान किया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को स्वयं अमेरिकी षड्यंत्रों के तहत उड़वा कर दुनिया में अमेरिका की बनती आतंकवादी छवि को धोकर निखारा और विश्व के सामने उसकी

पाली तालीबानी फौज को अपना दुश्मन सिद्ध कर सहानुभूति प्राप्त कर सका। दूसरा उसकी आड़ में ओसामा और तालीबानों के वहां छुपे होने का प्रपंच रच उस पर आक्रमण कर दक्षिण एशिया के उस महत्वपूर्ण अड्डे पर कब्जा कर बैठा जो उसके परमशत्रु रुस और चीन से सटा हुआ था। जहां तक भारत, पाकिस्तान और ईरान का सवाल था तो उसकी नजर में इन्हें वो अपने अस्तबल में पाले जानवरों से ज्यादा कोई औकात, बखत नहीं इनकी। सत्ताएं उसके इशारों पर नृत्य करती हो उसके नजर में यहां के प्रशासक क्या हो सकते हैं, पाले हुए टुकड़ाखोर श्वान।

ओसामा को तो उसे पकड़ना ही नहीं था उसे ओसामा की आड़ में अफगानिस्तान पर कब्जा कर उसके चारों तरफ बैठे भारत, रूस, चीन, ईरान को धमकाना, चमकाना करना था, वह पिछले 5 वर्षों से कर भी वही रहा है।

8-10-05 को अफगानिस्तान से सटी सीमा जिसमें आजाद कश्मीर, पाकिस्तान, भारत लगे हुए हैं। उस अमेरिकी गुंडे ने अफगानिस्तान की हिन्दू कुशाघाटी में 8 अक्टूबर से लेकर 30 नवम्बर 05 तक लगातार बम विस्फोट किए, उसमें उसके कई उद्देश्य पूरे हुए, जिसमें पाकिस्तान में बढ़ते मुशरर्फ विरोध को कम कर अपनी बदनामी रोकना, पाकिस्तानी, हिन्दुस्तानी जनता का ध्यान भूकंप से हुई क्षति और जनता के प्रति सहानुभूति की तरफ ध्यान बंटाना, ऊपर से उस गुंडे को अपनी दानशीलता दिखाने का मौका देना, उसने उन बम विस्फोटों जहां हिन्दुस्तान, पाकिस्तान व आजाद काश्मीर में तबाही मचाई, वहीं रूस और चीन को धमका भी दिया।

उसका उद्देश्य जो पूरा नहीं हुआ, वह चाहता था कि हिमालय की बर्फ पिघले और भारत में पर्याप्त बाढ से तबाही मचाई जाए, इसके विपरीत समय माया के श्री अजमेराजी का ध्यान 8-10-05 की तबाही को समझ पाता, 14-10-05 को उनके पिता के देहांत के कारण वो उलझ गए, उस तरफ सोच ही न सके, 29-10-05 को जब तेरहवीं सम्पन्न हुई, सारे मेहमान जाने में 2नवम्बर 05 निकली। जब उनका ध्यान उस तरफ गया तो माजरा समझ में आया कि अमेरिका हिन्दुकुशघाटी में भूगर्भीय परमाणु धमाके कर भारत, पाक, आजाद कश्मीर में कृत्रिम भूकंप से तबाही मचा रहा है।

उन्होंने भ्रष्टाचार की बेवसाइटों से जब इस सच्चाई को उजागर किया तो 03-11-05 से फिर भूकंपों का सिलसिला थमा।

अमेरिका जब इतना करने में सक्षम है, तो ओसामा को क्यों नहीं पकड़ा सका, ओसामा की आड़ में बुश ने चुनाव जीता, पूरी दुनिया में होती अमेरिकी थू-थू और आक्रोश को ठंडा किया किसके दम पर। ओसामा के ही दम पर।

कैसे अमेरिका इतने बड़े हथियार को बोल दे कि ओसामा मर गया। पिछले डेढ वर्ष से पुरानी रिकार्डिंग दिखाकर पूरे विश्व की जनता को आतंकित किया और मंतव्य पूरा किया जा रहा है। बेशक इसका नाटकीय पटाक्षेप करने के लिए कोई दूसरा ओसामा का हमशक्ल खड़ा कर उससे किसी मुसलमानी देश के चैनल से टी.वी. पर दिखाकर फिर धमकाएगा। बाद में अफगानी नागरिकों को आतंकी हमले दिखाकर उन पर प्रति आक्रमण कर उड़ाया जाएगा उसमें ओसामा की साइज और शक्ल सूरत के आदमी को मरा दिखा कर कोई पुनः उसके डुप्लीकेट से सद्दाम की तरह अदालती नौटंकी कर फांसी पर चढ़ा दिखाकर बहादुरी दिखाने का मौका देख रहा है, ताकि सच सदा के लिए ओसामा के डुप्लीकेट के साथ ही दफन हो।

शासन की हठधर्मी से दुःखी हैंडपंप टेक्निशियन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंडपंप तकनीशियनों की मांग

म.प्र. सरकार कर्मचारी हितैषी होकर इस सरकार में कर्मचारी अपने स्तर को बेहतर महसूस कर रहा है यह धारणा वर्तमान समय में कर्मचारी के विभिन्न आंदोलन के सरकार की कार्यशैली से निरमूल सिद्ध हो रही है। यह आरोप म.प्र. शासकीय तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष श्री कैलाश पंचौली एवं उनकी कार्यकारणी के प्रतिनधियिों ने म.प्र. टेक्निशयन हैण्डपम्प विभागीय जिला समिति के चल रहे धरना आंदोलन के 24 दिन कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा।

प्रदेश की मूलभूत समस्याओं के साथ स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है। तदनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था विभागीय कर्मचारियों पर निर्भर है। 4 लाख हैण्डपम्पों का रखरखाव प्रदेश में मात्र 21100 कर्मचारियों पर निर्भर है। शासन की नीति अनुसार अधिकतम एक कर्मचारी से 40 से 50 हैण्पपम्प का रखरखाव किया जाना चाहिए, परंतु जिले में एक कर्मचारी के हिस्से में अधिकतम 150 से 250 तक के हैण्डपम्प के संधारण करना पड़ता है। शासन की नीति अनुसार कर्मचारी का भ्रमण 8 से 10 कि.मी. का होता है, किंतु अभी वर्तमान में कर्मचारियों को 15 से 12 कि.मी. तक भ्रमण करना पड़ता है और यात्रा देयक भी अधिक दूरी का नहीं मिलता। अब गर्मी का मौसम भी सिर पर है जिस कारण कर्मचारियों को पूरे क्षेत्र का सघन भ्रमण करना पड़ता है। कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश है। अतः कर्मचारी 'करो या मरो' सिद्धांत के पालन पर अडिग है। पूरे प्रदेश में हड़ताल इसी सिद्धांत पर चल रही है।

प्रदेश में गर्मी के मौसम में यूं भी पानी की हमेशा परेशानी रहती है, इन्हीं कर्मचारियों की मेहनत एवं लगन से प्रदेश के ग्रामवासियों को पानी प्राप्त होता है। अतः शासन को

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थापित लगभग 3,92,525 (तीन लाख बयानवे हजार पांच सौ पच्चीस) हैण्डपम्पों को सतत रूप से चालू रखकर ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के राज्य शासन के लक्ष्य को मूर्तरूप देने वाले 2111 तकनीशियन अपनी सैद्धांतिक रूप से स्वीकार मांगों के निराकरण के लिए वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, किंतु मांगों का निराकरण आज तक नहीं हो पाया है, जबकि इनकी उपयोगिता और उपादेयता क्षमता से अधिक कार्य के उत्तरदायित्व से स्वयं स्पष्ट होती है।

उल्लेखनीय है कि समय-समय पर धरने रैली तथा

अवधि एक वर्ष से अधिक है, में आईटीआई सॅटिफिकेट निर्धारित है, को वेतनाम रुपए 4000-6000 स्वीकृत किया है यह अर्हता तकनीशियन रखते हैं। रुपए 4000-6000 वेतनमान के आदेश जारी किए जाने चाहिए।

2. पदोन्नति के संबंध में उल्लेखनीय है कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 29-3-77 की अनुसूची 2 भाग 4 में प्रावधान अनुसार 25 प्रतिशत उपयंत्री के पद आर्टिफिचर सहायक रिंग आपरेटर, कर्म सहायक एवं सर्वेयर तकनीकी कर्मचारियों से भरे जाने का प्रावधान है। इन्हीं के भांति तकनीशियनों को पदोन्नति देने हेतु भर्ती सेवा नियम में संशोधन कर पदोन्नति दी जावें तथा 8 वर्ष पर रुपए 4500-7000, 20 वर्ष पर रुपए 5000-8000 प्रवर श्रेणी पदोन्नति वेतनमान दिया जावें। वित्त विभाग की सहमति वर्ष 7 जून 2003 में प्राप्त हो चुकी है।

3 (अ) कार्यभारित सेवा के तकनीशियनों को कार्यभारित वाहन चालको तथा नियमित कर्मचारी की भांति सामान्य क्रमोन्नति का

म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग जनता को जल के नाम

सींच रहे बैंक बैलेंस

मंत्री, संत्री, यंत्री जालसाजी से

मंत्री चंद्रभान, यंत्री भाटिया, डबकारा, राजबडे, सूर्यवंशी

लोक स्वा. यांत्रिकीय विभाग में बैठे ग्रामीण के कार्य पालन यंत्री महामक्कार, भ्रष्ट भाटिया, बड़े-बड़े पाईप लाईन बिछाने, टंकी बनाने के ठेकों को अपने चहेते ठेकेदारों में बांटने, टेंडर न लगवाने के लिए पचास से ज्यादा ठेकों में छोटे-छोटे रुपए 2 लाख से कम के कार्यों में बदलकर अपने चहेते ठेकेदारों को देकर खुलकर वसूली और नियमविरुद्ध कार्य करवा रहे हैं।

इंदौर। इस हरामखोर को सूचना अधिकार में पत्र दो तो अनाप-शनाप शुल्क मांगता है। बिना किसी हिसाब-किताब के, पूछताछ करो तो ये निकम्मा बाद में पत्र को नस्ती करने का नोटिस भेज देता है। ये श्वान सरकार द्वारा बतौर इंजीनियर कार्य कर रहा है, परंतु कभी भी न तो आवेदन पढ़ता है न उसके हिसाब से जवाब देता है कानूनों के अनुसार।

नर्मदा प्रोजेक्ट के नगर निगम के इंजीनियर गोपाल डबकारा भी अपना भ्रष्टाचार का डमरू बजाकर भ्रष्टाचार का चारों तरफ तांडव करने में लगे हैं। पाइप लाइन बिना बिछाए ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया और बंदरबांट से धन हजम। इसी प्रकार नर्मदा पाइप लाइन के इनपुट सोर्स लाइन और जल वितरण की लाइनों

सिद्धांत पर चल रहा है।

प्रदेश में गर्मी के मौसम में यूं भी पानी की हमेशा परेशानी रहती है, इन्हीं कर्मचारियों की मेहनत एवं लगन से प्रदेश के ग्रामवासियों को पानी प्राप्त होता है। अतः शासन को इनकी मांगों को स्वीकार करते हुए प्रदेश की जनता को पानी के लिए परेशान होने से बचाएं। शासन की ओर से ईमानदारी से पहल करने की मांग कर्मचारी नेताओं द्वारा की गई है। तदनुसार वेतन विसंगति दूर कर ट्रेड कर्मचारियों को 4000 से 6000 वेतनमान, पदोन्नति एवं प्रवर श्रेणी कमोउन्नती शासन के निर्णय 7-7-98 कार्यभारित सेवा के टेक्निशियनों को दिए जाने वाले वेतनमान को सुधारने के लिए यह आंदोलन चल रहा है। आंदोलन को सफल बनाने में म.प्र. शासकीय कर्मचारी संघ के समस्य संबंध संगठनों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त है।

उपादेयता क्षमता से अधिक कार्य के उत्तरदायित्व से स्वयं स्पष्ट होती है।

उल्लेखनीय है कि समय-समय पर धरने, रैली, तथा आंदोलन के पश्चात राजनेताओं और शासन स्तर पर हुई चर्चाओं में मांगों पर घोषणाएं और आश्वासन प्राप्त हुए हैं, किंतु यह आश्वासन और घोषमाएं आज तक भी मूर्तरूप नहीं ले पाई है।

मजबूर होकर दिनांक 18 फरवरी से काम बंद हड़ताल का निर्णय कर्मचारियों द्वारा लिया गया। यहां शासन से अनुरोध है कि इनकी निम्नलिखित मांगों का निराकरण कराने में सहयोग करें।

1. उल्लेखनीय है वेतन विसंगति के संबंध में- ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसाओं पर शासन ने निर्णय लेकर वे पद जिन पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता हायर सेकंडरी संबंधित ट्रेड जिसकी प्रशिक्षण

के तकनीशियनों को कार्यभारित वाहन चालको तथा नियमित कर्मचारी की भांति सामान्य क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने अगस्त 2001 में जो वित्तीय खर्च का आंकलन मांगा था जो विभाग से भेजा जा चुका है। वित्त विभाग की सहमति वर्ष 7 जून 2003 में प्राप्त हो चुकी है। (ब) कार्यभारित सेवा के तकनीशियनों को नियमित सेवा में लिया जाए। नियमित सेवा में लेने पर वेतनमान समान है। (स) कार्यभारित सेवा के तकनीशियनों को नियमित वेतन 7.7.98 से देने के आदेश किए गए हैं, इसमें सुधार कर न्यायालयीन प्रकरण के आधार पर नियुक्ति के दिनांक से किया जाए। (द) विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी सहायकों का नियमितिकरण किया जाए।

विभिन्न विभागों में कार्यरत मैकेनिक एवं अन्य संवर्गीय कर्मचारियों को मिल रहे वेतनमानों का तुलनात्मक विवरण

तालिका जिनकी शैक्षणिक योग्यताएं आदि समान होते हुए भी वेतनमानों में भारी असमानता दर्शाने वाला पत्रक

क्रं.	विभाग/सेवा	पद	पांडे वेतन.	चौधरी वेतन.	वोरा वेतन.	केंद्रीय वेतन.	शैक्षणिक अर्ह./वांछनीय अर्ह.
1.	लो.स्व.यां.विभाग	रिग आपरेटर	280-480	740-1180	1290-2040	1400-2640	8वीं पास एवं 80,000 फिट/ 11वीं पास एवं 60,000 फिट/ आईटीआई मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक 40,000 फिट ड्रिलिंग का अनुभव.
2.,,	सहायक रिग	205-375	635-950	1200-1800	1320-2040	8वीं पास	4वर्ष का अनुभव 40,000 फुट ड्रिलिंग का अनुभव
3. तकनीकी शिक्षा		कर्म.शाला सहायक	246-450	740-1180	1240-2040	1400-2640	हा.से. एवं आईटीआई संबंधित ट्रेड से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण
4.	उद्योग संचालनाय	प्रयोगशाला	205-375	635-950	1200-1800	1320-2040	हा.से. उत्तीर्ण विषय विज्ञान से
5.	लो.स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग	मलेरिया तकनीकी	205-375	635-950	1200-1800	1320-2040	हा.से. उत्तीर्ण विज्ञान विषय से
6.	लो.स्वा.यां.वि.	हैण्डपम्प तकनीशियन	195-330	575-880	975-1650	1150-1800	हा.से. उत्तीर्ण एवं आईटीआई, दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

अतः उक्त शैक्षणिक योग्यता एवं वांछनीय अर्हताओं के आधार पर असमानता दर्शाने वाला पत्रक में स्पष्ट है कि समान योग्यताएं एवं अर्हताएं होते हुए भी हैण्डपम्प तकनीशियन को ही प्रारंभ से ही न्यूनतम वेतनमान देकर समानता की खाई को समाप्त करने संविधान के अनुच्छेद 311 एवं 45 में वर्णित नीति सिद्धांतों में समान कार्य वालों को समान पारिश्रमिक एवं सुविधाएं मिलनी चाहिए, के अनुरूप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के हैण्डपम्प तकनीशियन को वेतन 4000-6000 स्वीकृत किया जाए।

नघाविप्रा में 322.5

शेष पेज 6 का

बेशक उनके पाले हुए श्वानों में का.अ. इंगले मुख्य अभियंता पूर्व में एम.एल. रघुवंशी जो अब सेवानिवृत्ति के बाद ठेकेदार का पट्टा डालकर उनके कार्यालय में ही बैठ रहा है। वैसे अधीक्षण यंत्री सोनी भी ठेकेदार के यहां सेवानिवृत्ति के बाद सेवाएं दे रहे हैं। अपने प्रभावों से धड़ाधड़ बिल पास करवाकर भुगतान दिलवा रहे हैं। मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता म.प्र. भोपाल को सारी सच्चाइयां मालूम होने के बाद भी कोई जांच तो दूर देखने भी नहीं गए।

ओंकारेश्वर दायीं नहर में ह हमारा दावा है कि नहरों में पानी छोड़ने के बाद प्राक्कलन में घोषित सिंचाई की 50% सिंचाई भी नहीं की जा सकेगी, अंतिम छोर तक पानी पहुंचने की तो कप्लना ही निरर्थक है।सवाल ये उठता है कि चुनावी वर्ष में अंधेरनगरी चौपट राजा क्यों राज्य के धन को इस तरह बर्बाद कर ठेकेदारों के माध्यम से न केवल धन की बर्बादी वरन भविष्य में जनता की बर्बादी की तस्वीर बनाने पर तुले हैं।

मंत्री चंद्रभान, मंत्री भाटिया, डबकारा, राजबडे, सूर्यवंशी सब भ्रष्टाचार से सींच रहे बैंक खातों को

को भुगतान कर दिया गया और बंदरबांट से धन हजम। इसी प्रकार नर्मदा पाइप लाइन के इनपुट सोर्स लाइन और जल वितरण की लाइनों में लगभग 250 लीकेज और पाइप लाईन फूटने के बिल लगाए गए हैं जो अधिकांश फर्जी हैं। अधिकांश लीकेज में रुपए 50000/- के लगभग के बिल लगाकर रुपए ढाई करोड़ के गोलमाल के समाचार है। इस हरामखोर को भी सूचना के अधिकार में पत्र दो तो यह भी लिख कर देता है कि आहरण वितरण के अधिकार नगर निगम के पास हैं। हम तो केवल यहां नोटों की घास छील रहे हैं। हम आवेदक को क्यों बताएं, हमने कैसे, कब और कितनी छीली। हम डिग्री से इंजीनियर पर पेशे से तो ईटर हैं, दिमाग से चीटर, इस खेल के पुराने हिस्ट्री शीटर हैं। यही हाल इस विभाग के प्रमुख अभियंता से लेकर अंतिम ईकाई के रूप में बैठे उपयंत्रीयों तक के हैं। इंजीनियर अर्थात ईटर, दिमाग चीटर, भ्रष्टाचार के हिस्ट्रीशीटर तभी तो इंजीनियर।

इस विभाग के मंत्री चौधरी चंद्रभान भी अपने कारनामो को लिए कुख्यात होते जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में अवैध जमीनों के कब्जे, बिकवाने के मामले में कुछ प्रकरण लोकायुक्त की जांच के घेरे में है। विभाग में पाईप लाईन आपूर्ति के ठेके भी अपने नागपुर के मित्र की फैक्ट्री से स्तरहीनता के उपरांत भी खरीदे गए, करोड़ों का भुगतान और बंदरबांट की गई।

म.प्र. लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में भी दो अलग-अलग विभाग हैं। ये सारी कहानी सिविल मेंटीनेंस की थी, यहां एक यांत्रिकीय विभाग और हैं जिसमें संभाग स्तर पर ही एक कार्यपालन अभियंता बैठता है, जिसमें इंदौर व उज्जैन दाहिमा विराजमान हैं। इसके अंतर्गत छह जिले इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ है। इसमें अधिकतर कार्य हैंण्डपम्प खोदना, लगाना है। इस विभाग के पास अपनी ड्रिलिंग मशीनें हैं। यहां भी एक ही कार्यपालन यंत्री वर्षभर में मशीनों के रखरखाव और डीजल व ट्यूबवैल खोदने के लिए करोड़ों रुपए के बिलों का भुगतान करता है। जिसमें शुद्ध 30 से 40 प्रतिशत की जालसाजियां होती है।

इस का.अ. को सूचना के अधिकार में जितने भी पत्र दिए गए ये इंजीनियरिंग उत्तीर्ण आवेदन के अनुसार कभी भी जवाब नहीं देते, एक मुश्त 15000/- रुपए का बिल देते हैं। चूंकि भारी भ्रष्टाचार किया है तो अपनी भ्रष्ट करतूतों को खोलने वाली कोई सूचना अधिकार के पत्र की भाषा इन श्वानों को कैसे और क्यों समझ आएगी? इसलिए आवेदक को ये भ्रष्ट आतंकी आतंकित करते हैं। यही हाल इस विभाग के यांत्रिकीय विभाग उज्जैन का है, वहां भी पत्रोत्तर कभी भी तरीके से नहीं दिया जाता, ताकि सूचनाएं न देनी पड़े।

म.प्र. लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग

कां.यं.राणे, मु.अ. अग्रवाल आंख मींच कर रहे भुगतान

अ. राणे के कदम-कदम भ्रष्टाचारों पर पूरी लिखी जा सकती है रामायण

इंदौर। सं.-2 में हाल ही में पदस्थ का यंत्री राणे जहां भी गए अपने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। लेबड़, रतलाम मार्ग पर किए गए पेंचवर्क में रुपए 50 लाख के पेंचवर्क 50 दिन भी नहीं चले, उखड़ गए, वर्तमान में इंदौर, सांवेर, उज्जैन में किए जा रहे कार्यों में एक तरफ मार्ग बन रहा है तो वहीं मार्ग 15 दिन भी ढंग से नहीं चल पा रहा और उखड़ता भी जाता है। जिस मार्ग पर पहले कार्य किया जा चुका था उसी पर पुनः कार्य करवाया जा रहा है। का.अं. राणे से जब पूछताछ की तो रहते हैं पूरा बनेगा, पूर्व के रुपए 1 करोड़ अर्थात सब पानी में, जैसा कि समय माया ने छापा था। अभी भी 18 से 20/2 तक मार्ग 27 से 29/2 तक सांवेर बायपास का मार्ग पर 6 सित. से फरवरी 29 तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। यही हाल 35 से 37 कि.मी. तक का भी है।

पूरे मार्ग पर 9 मी. सड़क के दोनों ओर कहीं पर भी डेढ़ मी. लगभग 5 फुट की पट्टियां ही नहीं है, 5 के स्थान डेढ़ फुट से 2'- 3' की पट्टियां भी ढंग से नहीं भरी गई है। दोनों ओर 30'-30' फीट चौड़े वृक्षों के लगाने की भी व्यवस्था और कोई गैंग भी कार्य नहीं कर रही है जो सोचनीय है।

हाल ही में एक विधानसभा प्रश्न क्र. 2505 में इस भ्रष्ट राणे की हरामखोरी का मामला उठा है जो कि कानवन मांगोद मार्ग 47 कि.मी. के निर्माण बाबद, जिसमें इसने ठेकेदार को रुपए 3 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया गया है। वह मार्ग केवल कागजी बनकर रह गया है। ठेकेदारों को आंखों पर बैठाकर शासकीय धन की लूटपाट का ये मामला जब हमारी नजर में आया तो आनन-फानन धार जाकर राणे ने एक रिपोर्ट फाइल कर सारा मामला अपने मातहत एसडीओ और उपयंत्री पर डालने की कोशिश की है।

अग्रवाल

राणे

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग धार संभाग धार

क्रमांक 68/ तक/ निरीक्षण/08 धार दिनांक 5/1/2008

प्रति,

1. श्री डी.के. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भ/प) उपसंभाग बदनावर
2. श्री वी.के. श्रीवास्तव उपयंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) उपसंभाग बदनावर
3. श्री अलसिंह भिडे लोक निर्माण विभाग (भ/प) उपसंभाग सरदारपुर
4. श्री महेश सोनी उपयंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./प.) उपसंभाग सरदारपुर

विषय- कानवन मांगोद मार्ग लम्बाई 47.00 किमी के निर्माण बाबत।

संदर्भ- अनुबंध क्रमांक 4/ईई/07-08 मेसर्स राजेश अग्रवाल अ-5 कांट्रेक्टर

उपरोक्त संदर्भित अनुबंध के अंतर्गत विषयांकित मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर कानवन मांगोद मार्ग किमी 1 से 26 तक लम्बाई 26. कि.मी. तक लोक निर्माण विभाग उपसंभाग बदनावर अंतर्गत एवं कि.मी. 27 से 48/2 तक लम्बाई 21.00 कि.मी. का मार्ग निर्माण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सरदारपुर एवं उपयंत्रियों के द्वारा अनुबंधित एजेंसी से कराया जा रहा है।

अनुसार चल रहा है। विभागीय अधिकारी सिर्फ बिल पर ही हस्ताक्षर करना अपनी ड्यूटी समक्ष रहे हैं।

7. मार्ग पर चौडीकरण कार्य में प्रयुक्त मटेरियल की गुणवत्ता एवं चौड़ीकरण कार्य की चौड़ाई एवं लेयर में संघनीकरण पर भी विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

8. कि.मी. 28,29 में जीएसबी कार्य की गुणवत्ता घोर आपत्तिजनक होकर रिजेक्ट करने योग्य होने से ठेकेदार प्रतिनिधि को साईट पर निर्देशित किया गया।

9. कृपया नोट करें यदि ठेकेदार अपनी मनमर्जी से एक तो उसको फायदे वाले कार्य की मात्रा ज्यादा बढ़ाकर कार्य करता है एवं कार्य की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं देता है। विशेषकर जीएसबी की गुणवत्ता एवं डब्ल्यूबीएम मेटल की ग्रेडिंग एवं सीमेंट क्रांकीट मार्ग में डी.एल.सी. के मटेरियल की गुणवत्ता पर ध्यान न देकर कार्य करता रहता है और अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशों के बावजूद न तो अनुविभागीय अधिकारी एवं न ही उपयंत्री साईट पर जाकर कार्य की गुणवत्ता को कंट्रोल करते हुए कार्य करा पाते हैं एवं न ही अपने अधीनस्थ समय पालको को कार्य स्थल पर भेज पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में खराब कार्य के लिए दोषी कौन रहेगा? कृपया स्पष्टीकरण देवे।

10. क्यों न आपके द्वारा अपने कर्त्तव्यों का पालन न करने हेतु आपको दोषी माना जाकर आपके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भिजवाया जाए।

11. यहां यह कथन कहां तक सत्य है कि ठेकेदार अपनी मनमर्जी से निर्माण कार्य कर रहा है, जबकि आप लोग एवं आपके अधीनस्थ उपयंत्री/समयपालक निरंतर साईट पर जाते ही

८३००० क्विं. गेहूं आयातित, नमूना फेल, फिर भी जनता में बांटा

खा.नि. परमार, कदम-कदम भरमार, भ्रष्टाचार

खाद्य नियंत्रक परमार की भ्रष्ट कार्यशैली से जनता चारों तरफ परेशान हो रही है, पर यह बंदा आंख मींचे चारों तरफ से वसूली में जुटा है।

इंदौर। भारतीय खाद्य निगम, इंदौर केंद्रीय भंडार गृह से गरीबों और राशन दुकानों पर बांटा जाने वाला आयातित 83000 क्विंटल गेहूं जो कि लाल था खाद्य निरीक्षक ने जो पिछले माह तीसरे सप्ताह जो उस गेहूं के नमूने लिए तो इस हरामखोर परमार ने उन नमूनो को खाद्य मिलावट निवारण अधि. 1954 प्रिवेन्शन ऑफ फूट एडल्टरेशन एक्ट. 1954 की विभिन्न धाराओं में नहीं भरने दिया। इन्हें इस अधि. के विपरीत के औपचारिकतापूर्ण करने की कार्यवाही में भरवाया गया। वो दोनों नमूने भोपाल की म.प्र. की खाद्य प्रयोगशाला ने मानव खाद्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। इसके विपरीत इस परमार, जिलाधीश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री, शिवराज और मुख्य सचिव के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए उस गेहूं में मोटा लेन-देन करके गेहूं का जो कि पूर्णतः अनुपयोगी मानव स्वास्थ्य के लिए अहितकारी होने पर भी बंटवा दिया।

गैस, मिट्टी का तेल, पेट्रोल पम्प, राशन दुकानों से वसूली

यदि ये दोनों जिलाधीश व खाद्य नियंत्रक उन नमूनों को खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 की धाराओं के अंतर्गत नमूने भरवाते और नमूने के फेल होने पर स्वाभाविक था खाद्य एवं औषधि विभाग का निरीक्षक लोंगरिया उनके खिलाफ चालान पेश करता, जिसमें भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारगृह के अधिकारियों के साथ ही खाद्य नियंत्रक परमार और जिलाधीश भी लपेटे में आ जाते, जिससे इनकी गिरफ्तारियां भी संभावित थीं।

जबकि यही नमूने जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर इसी पीएफए

आंखों पर बैठाकर शासकीय धन की लूटपाट का ये मामला जब हमारी नजर में आया तो आनन-फानन धार जाकर राणे ने एक रिपोर्ट फाइल कर सारा मामला अपने मातहत एसडीओ और उपयंत्री पर डालने की कोशिश की है।

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय

(1) प्रश्न क्रमांक - 2505
(2) विभाग से उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि- 03-03-2008
(3) सदन में उत्तर देने की तिथि 11-3-2008
(4) वर्ग जिसके लिए यह तिथि नियत है
04 लोक निर्माण विभाग

विषयः कानवन मांगोद मार्ग के संबंध में।

तारांकित प्रश्न

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि

प्रश्न

(क) कानवन मांगोद मार्ग किस योजना अंतर्गत कितनी लागत से किस ठेकेदार द्वारा किन नियम एवं शर्तों पर करवाया जा रहा है? और कार्य पूर्ति की समय सीमा क्या है? ठेकेदार से अनुबंध और कार्यपालन तथा भुगतान किए गए बिलों की राशि की जानकारी देवें?

(ख) क्या निर्माणाधीन मार्ग पर घटिया कार्य और लापरवाही पाए जाने के कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, धार संभाग द्वारा दिनांक 5-1-08 को पत्र क्रमांक 88/तक/निरीक्षण/08 दिया गया? यदि हां तो संबंधित ठेकेदार और अन्य पर क्या कार्यवाही की गई? पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें?

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, पश्चिम परिक्षेत्र, इंदौर
पृष्ठांकन क्रमांक 15/2/विस/बजट सत्र/ फरवरी-अप्रैल/08 इंदौर दिनांक 22-02-08

प्रतिलिपि-

(1) अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मंडल इंदौर/खंडवा की ओर प्रश्न का उत्तर दिनांक 25.02.08 के पूर्व भिजवाने की व्यवस्था करें।
(2) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग धार की ओर प्रश्न का उत्तर दिनांक 25.02.08 के पूर्व प्रस्तुत करें।
(3) कार्य/ बजट/सामान्य/ स्थापना शाखा परिक्षेत्र कार्यालय इंदौर।

निर्माण विभाग उपसंभाग बदनावर अंतर्गत एवं कि.मी. 27 से 48/2 तक लम्बाई 21.00 कि.मी. का मार्ग निर्माण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सरदारपुर एवं उपयंत्रियों के द्वारा अनुबंधित एजेंसी से कराया जा रहा है।

आज दिनांक 2-01-08 को श्री डी.के. सोलंकी अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग बदनावर एवं श्री अलसिंह भिडे अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग विभाग उपसंभाग बदनावर एवं श्री अलसिंह भिडे अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सरदारपुर के साथ ठेकेदार के इंजीनियर प्रतिनिधि श्री दिनेश सिंह के साथ मार्ग का निरीक्षण किया गया, मार्ग पर कोई उपयंत्री एवं समयपालक उपस्थित नहीं पाया गया। मार्ग पर निम्नानुसार कार्य के दौरान कमियां पाई गई।

1. मार्ग पर प्राक्कलन की निर्धारित मात्रा अनुसार अर्थवर्क एवं जी.एस.बी. अनुसार कार्य नहीं कराया जा रहा है। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहा है।

2. मार्ग पर ठेकेदार द्वारा की जा रही अधिक अर्थवर्क एवं जी.एस.बी. की मात्रा एवं अनुबंधित टेंडर दर के कारण निर्माण कार्य की लागत में हो रही वृद्धि पर उपसंभागीय अधिकारियों का कोई कन्ट्रोल नहीं देखा गया।

3. ड्रेनेज लेयर में जी.एस.बी. की थिकनेस 10 से.मी. तक सीमित रखने के निर्देश पर कोई कंट्रोल नहीं रखा जा रहा है।

4. जी.एस.बी. में प्रयुक्त किए जा रहे मटेरियल की गुणवत्ता पर कोई विशेष टेस्टिंग एवं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके लिए दोनों ही उपसंभाग के एसडीओ एवं कार्य पर पदस्थ उपयंत्री दोषी है।

5. बदनावर उपसंभाग के उपयंत्री श्री वी.के. श्रीवास्तव से साईट स्थल से दूरभाष पर चर्चा की तो उनके द्वारा बताया कि ठेकेदार उनकी नहीं सुन रहा अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहा है, इसलिए वे साईट पर नहीं जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में बिना टेस्टिंग के. उपयंत्री श्रीवास्तव द्वारा अभी तक बिल बनाकर क्यों प्रस्तुत किए जाते रहे हैं स्पष्टीकरण देवें।

6. बिडवाल गांव में सीमेंट-क्रांकिट कार्य ईंग्र-40 रोड का कार्य प्रगति पर प्रयुक्त किए जाने वाले मेटल की ग्रेडिंग पर एवं सेण्ड की गुणवत्ता पर कोई कंट्रोल नहीं पाया गया? एवं सीमेंट क्रांकिट कार्य पर कोई विभागीय कर्मचारी उपस्थित नहीं पाया गया। ऐसा लग रहा कि निर्माण कार्य विभागीय कंट्रोल में न होकर ठेकेदार की मर्जी को भिजवाया जाए।

11. यहां यह कथन कहां तक सत्य है कि ठेकेदार अपनी मनमर्जी से निर्माण कार्य कर रहा है, जबकि आप लोग एवं आपके अधीनस्थ उपयंत्री/समयपालक निरंतर साईट पर जाते ही नहीं है। इसके लिए दोषी कौन है।

12. जब आप ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्य जैसे जीएसबी एवं डीएलसी एवं कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एवं ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की माप बगैर कटौत्रा किए प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में खराब कार्य के लिए दोषी कौन रहेगा? कृपया स्पष्टीकरण देवें?

13. यदि आपके द्वारा कार्य की गुणवत्ता पर कंट्रोल नहीं की जा पा रही है, जबकि आप बराबर वेतन पा रहे है एवं आप ठेकेदार द्वारा उनकी मनमर्जी से किए गए कार्य को देयक भी बिना कोई कटौत्रा किए नियमानुसार भेज रहे हैं। तो उक्त भुगतान के लिए आप पूर्णतः जिम्मेदार रहेंगे।

प्रयुक्त मटेरियल के बिना लेबोरेटरी टेस्टिंग एवं बिना फील्ड टेस्टिंग के आपके द्वारा प्रस्तुत बिल के लिए आप ही पूर्णतः जिम्मेदार रहेंगे।

15. यदि भविष्य में शेड्यूल से किए गए अधिक कार्य की मात्रा की कोई रिकवरी प्रस्तावित की जाती है तो सही तरीके से संबंधित उपयंत्री एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध विविध अग्रिम डालकर रिकवरी प्रस्तावित की जावेगी।

16. भविष्य में क्यों न आपके द्वारा कराए गए कार्य जिस पर आपके द्वारा ध्यान नहीं रखा गया आपके विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाकर भुगतान किया जावेगा कृपया नोट करे।

क्रमांक/ तक/निरीक्षक/08
धार, दिनांक/ /2008

प्रतिलिपीः-

1. श्री राजेश अग्रवाल अनुबंधित ठेकेदार अ-5 इंदौर की ओर लेख कर निर्देशित किया जाता है कि आप संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं संबंधित उपयंत्रियों के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें एवं अपनी मनमर्जी से कार्य करना कृपया बंद करें, अन्यथा भविष्य में होने वाले विवाद की स्थिति के लिए आप ही व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, कृपया नोट करें।

यह अ. राणे शूकर द्वारा अपनी खाल बचाने का प्रयास है,क जो पत्र से स्पष्ट झलकता है, फिर भी मु.अ. अग्रवाल अपना हिस्सा डकार कर चुप है। आखिर क्यो?

भंडारगृह के अधिकारियों के साथ ही खाद्य नियंत्रक परमार और जिलाधीश भी लपेटे में आ जाते, जिससे इनकी गिरफ्तारियां भी संभावित थीं।

जबकि यही नमूने जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर इसी पीएफए एक्ट 1954 के अंतर्गत ही भरे गए।

गैस-इंदौर में ईंधन गैस के आपूर्तिकर्ता 25 वितरकों से परमार को हर महीना रुपए 25000/- मिलने की सूचनाएं विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुई है। स्वाभाविक है प्रबुद्ध पाठकगण समझ गए होंगे कि कालाबाजारी के पीछे जिला प्रशासन के भ्रष्टाचार से अर्द्धमुद्रित नेत्रों से वसूली के बाद वितरकों को कालाबाजीर से वसूली की छूट देनी ही पड़ेगी। अन्यथा अगले महीने रुपए 25000/- कौन और क्यों देगा?

इस गैस कांड को लेकर कुछ खाद्य निरीक्षकों जिसमें सेंगर व अन्य अपने दो-तीन निजी चेलों को लेकर मालवामिल क्षेत्र में अधिकारों के विपरीत घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की आड़ में हर शाम डकैती डालते-डालते वहां पहुंच गए। लेन-देन की बात पक्की होने के बाद मामला बिगड़ गया और जनवरी 08 में ठुकाई-पिटाई हो गई।

मामले की गहराई में जाने पर मालूम पड़ा कि खाद्य नियंत्रक सो सीधा गैस वितरकों से रुपए 25000/- हर माह डकार लेता है तो नीचे बैठे कुछ निरीक्षक, सहा. खाद्य आपूर्ति अधिकारी जिसमें मीना जो वर्षों तक कुंडली मारे बैठे रहे, बाद में स्थानांतरण होने पर लूट का कुछ हिस्सा लुटाकर पुनः कुंडली मार इस प्रकार से दुकानदारों, ठेलेवालों, रिक्शाचालकों व घरेलू गैस का इस प्रकार व्यावसायिक उपयोग करने वालों से ये सफेदपोश सरकारी डकैत 6 बजे से लेकर विभिन्न इलाकों में गुट बनाकर घूमते और हर प्रकरण में रुपए 2 से 5 हजार के 5-7 प्रकरण बना कर रुपए 10 से 20 हजार इकट्ठे कर ही घर लौटते हैं।

खाद्य निरीक्षक सेंगर की इस प्रकार की डकैती की सन 2003 की घटनाएं समय माया पहले भी छाप चुका है। यही हाल उज्जैन, देवास, धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, झाबुआ, बुरहानपुर आदि में भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जिलाधिकारी से लेकर खाद्य निरीक्षकों की वसूली के चल रहे हैं।

अधिकांश शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों की कारों में अवैध गैस किटों से चलाई जा रही कारो में खुलकर घरेलू गैस का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें जिला सत्र न्यायालयों के सम्मानीय कहे जाने वाले न्यायाधीश, लोक अभियोजक तक शामिल हैं। कितनों को गैस किट वाली कारें पकड़ी गई। जिलाधीश से लेकर खाद्य नियंत्रक व सहा. खाद्य अधिकारी, निरीक्षक बतलाएं।

मिट्टी के तेल की पेट्रोल पम्पों पर लूट, वसूली और मिलावट की छूट अगले अंकों में.....

समाचार ओर भी हैं, पढ़ते रहिये
'समय-माया'

वि.व.सं. के २००० करोड़ डकार जाता है वन विभाग

150 शेर भी नहीं है प्रदेश में

इंडियन फारेस्ट (ईटिंग) सर्विस के अधिकारी बढ़ते गए, वन प्राणी घटते गए

भारत में घटते शेरों, तेंदुओं व अन्य सहस्त्रों वन प्राणीयों के संदर्भ में प्रधानमंत्री मनमोहन ने प्रदेश के मुख्यमंत्रीयों से चर्चा की ओर शेरों की घटती आबादी के बारे में चिंता व्यक्त की। वर्तमान में शेर, तेंदुओं की आबादी के बारे में तो चिंता व्यक्त की जा रही है, परंतु अन्य वन्य प्राणियों के बारे में न केवल वन विभाग पूरे देश के प्रदेशों का वरन 28प्रदेशों को वन मंत्रालयों से लेकर राष्ट्र के पर्यावरण और वन मंत्रालय तक सब चुप्पी साधे हैं, जबकि हिरण, नीलगाय, सांभर, भालू जैसे बड़े जानवरों से लेकर जंगली सूअर, सोन कुत्ते, खरगोश, सियार जैसे मांद में रहने वाले जानवरों का न केवल खुलकर शिकार धड़ल्ले से हो रहा है वरन् इन जानवरों की खालों का व्यापार भी चोरी-छिपे धड़ल्ले से चल रहा है। इन सबके विपरीत केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से लेकर राज्यों,वन एवं पर्यावरण मंत्रालयों तक मंत्रीयों व सचिवों से लेकर वन विभागों के बीट गार्ड तक सब नोंचने-खाने में आंख मींच कर जुटे हैं।

म.प्र. के वन मंत्रालय के प्रधान वन संरक्षक खरे से भोपाल से चर्चा हुई, शेरों के संबंध में उन्होंने माना कि 300 शेर हैं। इसके विपरीत शेरों की गणना पद्धति में शेरों के पंजों के निशान व कैमरे के फोटो लेने का तरीका जो गिनती करने का है पूर्णतः संदिग्ध है।

इस संबंध में भोपाल के प्रधान मुख्य संरक्षक वन कार्यालय में बैठे एक वन संरक्षक से जो चर्चा हुई थी उसमें उन्होंने माना कि गणना पद्धति पूर्णतः संदिग्ध है। साथ ही संख्या भी जो वर्तमान में दी जा रही है वह भी आंकड़ों की बाजीगरी ही है। वर्तमान में खुले जंगलों में

मुश्किल से 50 से 70 शेर ही हैं। साथ ही पेंच, कान्हा (सिवनी) कान्हा (पन्ना) और शिवपुरी के जंगलों में भी कुल मिलाकर भी 50-60 शेर से ज्यादा नहीं है।

प्रदेश में घने जंगलों का अंधाधुंध कटाई के कारण सन 1990 की तुलना में 40प्रतिशत और 1970 की तुलना में 15 प्रतिशत ही बचे हैं, जो शासन वैसे इस बार की शासकीय डायरी में वो आंकडा दिया ही नहीं है। फिर भी पूरे प्रदेश के 3,0800 वर्ग कि.मी. में 3200 वर्ग कि.मी. से ज्यादा पूरे प्रदेश में वन नहीं है। इसकी सत्यता उपग्रह से प्राप्त छाया चित्रों से पता लगाई जा सकती है।

एक तरफ म.प्र. के वनों में जहां शेर, तेंदुओं के साथ सभी वन प्राणियों की संख्या शनैः-शनैः घट रही है कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी है, जिनका अहसास तक वन विभाग के शीर्ष से लेकर निचले जिलास्तर पर बैठे अधिकारियों को भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण केंद्रीय व प्रादेशिक स्तर पर जैव संरक्षण के लिए शासकीय स्तर पर पिछले 60वर्षों में कोई ठोस कार्य के साथ संगठन की भी स्थापना वन विभाग में नहीं हो सकी है। जैव विविधता एवं जैव प्राद्योगिकी बोर्ड बना भी है तो उसने पिछले 3-4 वर्षों में कोई ठोस कार्य नहीं किया, क्योंकि वहां न तो अभी कोई स्टॉफ है, ज्यादा न ही कार्यों की कोई ठोस रूपरेखा है। वहां बैठे अपर सचिव से लेकर 5-7 व्यक्तियों में न तो कोई बड़ा वैज्ञानिक, इतिहासकार है, जैव विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी जैसे आवश्यक स्टॉफ का ही अभाव है। तो वन में पाए जाने वाले वन प्राणियों की सुध लेने का तो सवाल ही नहीं है। सैकड़ों पशु, पक्षियों, रेंगने वाले, मांद में रहने वाले जानवरों के संरक्षण का तो ये वन विभाग के वनैलों से दूर-दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है।

म.प्र. वन विभाग को विश्व वनप्राणी संघ से हर वर्ष अमेरिकी डॉलर 2000 करोड़ मिलते थे, जिसका ये वनैले सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक से

बैठा दिए गए हैं।

यही कारण था कि वन कर्मचारी संगठनों ने बढ़ते वनैले अधिकारियों की संख्या घटती कर्मचारियों की संख्या को लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन किए हैं। जहां 1990 में 13990 वन कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या थी, वहीं वर्तमान में 9000 से भी कम कर्मचारी हैं। बढ़ते वनैले अधिकारियों का भ्रष्टाचार, घटते कर्मचारियों की संख्या के कारण वन माफियाओं, द्वारा वनों को तेजी से साफ किया जाकर भूमियां पट्टे पर देकर खुलकर कृषि की जाने के साथ ही नेताओं, बड़े उद्योगपतियों, भास्कर जैसे मीडिया के पूंजीपतियों ने भी जंगलों की सफाई कर अपने संस्थानों की स्थापनाएं कर दी है।

शासकीय तौर 132 वर्ग कि.मी. के जंगलों को विकास के नाम पर पुनासा, ओंकारेश्वर बांधों, सिंचाई की नहरों, बांधों के डूब क्षेत्रों के कारण भी साफ किए गए, पर वास्तविकता में यह आंकडा 300 कि.मी. से ज्यादा है। 132 वर्ग कि.मी. तो वह क्षेत्र है, जिसे शासन व केंद्र शासन से स्वीकृति के बाद काटा गया है, पर वास्तविकता में कटाई के नाम पर वन विभाग के वनैले अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से कटाई करने वाले ठेकेदारों ने दुगुनी से ज्यादा अनाप-शनाप कटाई की है। जिसका ताजा उदाहरण खरगोन जिले की बड़वाह तहसील और सनावद में ओंकारेश्वर नहरों के दोनों तरफ मय प्रमाण देखे जा सकते है। जहां तक वन मंत्री जयंत मलैया, राज्यमंत्री विजय शाह का सवाल है तो एक को भ्रष्टाचार

म.प्र. प्रदूषण फैलाओ मंडल में सूचना अधिकार आवेदन से तूफान

महाभ्रष्ट प्रदूषण मिश्रा, नचाता है पूरा मंडल

इंदौर का प्रदूषण नियंत्रण मंडल सच्चे अर्थों में नियंत्रण मंडल नहीं प्रदूषण फैलाओ मंडल है, जिसमें पूर्व में 10वर्षों से ज्यादा समय कुंडली मारे बैठा मिश्रा ज्यादा हल्ला मचने पर 8-9 माह के लिए भोपाल में अटेच रहकर पिछले लगभग 1 वर्ष से पुनः इंदौर में भ्रष्टाचार से लूट धन के बल, धन लुटाकर पुनः इंदौर में आकर जम गया है।

इसके आते ही इसकी पुरानी गैंग जिसमें वैज्ञानिक प्रयोगशाला, मुखिया अधिकारी व अन्य सहकर्मी

ये वही धूर्त लुटेरा है जिसने सन 2003-04 में दालमिलों से अनापत्ति और अनुज्ञप्ति के नाम विधायकों के साथ मिलकर रुपए 4 करोड़ डकार लिए थे। इस प्रदूषण विभाग में जब तक मिश्रा बैठा है कार्य प्रदूषण नियंत्रण करना नहीं वरन प्रदूषण फैलाने वालों को धन के बदले संरक्षण प्रदान करना है। इसके सबसे बड़े उदारहणों में पोलोग्राउंड की इप्का फैक्ट्री है, जिसकी बदबू से बाणगंगा, मरीमाता, पोलोग्राउंड,

किया जा रहा हो और ब्लैक मेलिंग का आरोप लगा रहा हो।

वैसे मिश्रा के स्टॉफ के अधिकारियों श्रीवास्तव व अन्य ने जो संख्या में 5-6 थे घेरकर लड़ाई झगड़े और मारपीटी करने की 11 फरवरी 08 को जब तैयारी कर ली थी। जब वो धार के क्षेत्रीय कार्यालय से पैसे जमाकर लौट रहे थे। उनको ये अहसास हो चुका था, इसलिए वो चुपचाप घूरती आँखों के बीच से पहले प्रदूषण मंडल के भ्रष्टाचार से प्रदूषित के

पुनः इंदौर में आकर जम गया है।

इसके आते ही इसकी पुरानी गैंग जिसमें वैज्ञानिक प्रयोगशाला, मुखिया अधिकारी व अन्य सहकर्मी जो वर्षों से कुंडली मारे इंदौर में जमें है पुनः लूटमार से प्रदूषण मंडल के नियमों और कानूनों के हथियार के लिए पूरे इंदौर क्षेत्र में सक्रिय हो गई है। इस संबंध में श्री अजय शुक्ला ने कोई पत्र सूचना के अधिकार में दिया था, जिसमें इन भ्रष्टों ने उसे आनन-फानन में रुपए 4300/- जमा करने के लिए कहा, अगले बंदे ने रुपए 4300/- बिना पूछताछ के जमा भी कर दिए, जबकि कुल छाया लिपियों की अधिकतम रुपए 2 से कीमत मात्र 2600 रुपए ही होती है। अर्थात् उस आवेदक से रुपए 1700/- जमा करवा लिए गए, इसके बाद भी इन धूर्त, हरामखोरों की फौज ने उस आवेदक को 15 दिन के बाद भी उसे दस्तावेज नहीं दिए गए।

प्रदूषण मंडल के नियमों के अंतर्गत वर्तमान में हर किसी को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना और अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे उसकी इकाई जल या वायु किसी का प्रदूषण नहीं फैला रही हो। ये हरामखोर अनापत्तिप्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति के नाम पर छोटी इकाइयों से अनापत्ति और अनुज्ञप्ति के शुल्क के उपरांत भी रुपए 10000/- नए के लिए और 15,000/- पुर्ननवीनीकरण के नाम पर खुलकर वसूल रहे हैं। इस प्रकार ये अधिकारी मिश्रा करोड़ों रुपए हर वर्ष वसूल रहा है। स्वाभाविक है लूट रहा है तो पुनः इंदौर आने और जमे रहने के लिए भोपाल मुख्यालय में भी लाखों रुपए बांट कर इंदौर में कुंडलीमारे बैठा है।

प्रदान करना है। इसके सबसे बड़े उदारहणों में पोलोग्राउंड की इप्का फैक्ट्री है, जिसकी बदबू से बाणगंगा, मरीमाता, पोलोग्राउंड, परदेशीपुरा पिछले कई वर्षो से परेशान है। पर इसे इन सबसे क्या वहां से बराबर महीना मिलता है। इसकी बला से।

यही हाल प्लेथिको, सांवेर रोड की फैक्ट्रीयों में अंनेकों दवा फैक्ट्रियों के जल और वायु प्रदूषण से वर्षों से लोग न केवल आतंकित हैं वरन उनके छोड़े गए प्रदूषित घातक जल से सांवेर रोड की बस्ती में लगे अधिकांश हैण्डपम्पों में रंगीन प्रदूषित पानी निकल रहा है, आखिर ये श्वानों की फौज, जिसमें मिश्रा तो पहले भी 10 वर्षों से ज्यादा इंदौर में रहा है क्यों आंखें मूंदे बैठी है, क्योंकि सबसे इनको महीने के टुकड़ों की वसूली मिलती है।

यही कारण है कि एम.आर.-10 का वह नाला जो रेल क्रासिंग के पास से गुजरता है बदबू से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां बैठे धूर्त शूकरों की कार्यप्रणाली कैसी है। ये वही नाला है जिसके किनारे बसे 15 कि.मी. दूर के गांवों, भांग्या, जाख्या में अधिकांश लोग खुजली की बीमारी से पीड़ित हैं। तो फिर ये प्रदूषण मंडल यहां क्या भाड़ झोंक रहा है।

वैसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2/1/2000 को जो निर्णय दिया वो हरामखोर महाभ्रष्ट प्रदूषक मिश्रा जैसे अधिकारियों के कारण ही दिया था कि जब पूरे देश के हर राज्यों में प्रदूषण मंडल बैठे हैं तो कैसे प्रदूषण फैल रहा है। अगर प्रदूषण फैल रहा है तो फिर इन मंडलों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। इंदौर के क्षेत्रीय कार्यालय के इस अधिकारी मिश्रा के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि प्रदूषण मंडल में कोई भी अध्यक्ष हो, मंत्री हो, उसे मिश्रा अपने

भ्रष्टाचार के धन के बल पर न केवल नचाता है वरन कानूनों की भी तोड़ मरोड़कर अपने हित साधने की व्याख्या करवा कर अपनी नींव पुख्ता करने में लगा रहता है। इसके पूर्व सन 2001-02, 03 में व्ही.के. जैन को ये एक तरफ धन बांटता रहा दूसरी तरफ उसकी लोकायुक्त जांच में अपने कुकर्मों से उसके गले में घंटी बांधकर उसको निपटाया। बाद में श्री एस. दुबे आए तो उनको भी एक तरफ धन बांटता रहा दूसरी तरफ धन डकारने के चक्कर में वो इस धूर्त की धूर्तता को समझे बिना इसके पापों पर पर्दा डालते रहे बाद में वो भी इस शातिर के चक्कर में निपट गए। अब गौतम जो अध्यक्ष है भी इसी के चक्कर में शनैः शनैः उलझते हुए अपने चारों तरफ इसकी भ्रष्ट मायाचारिता का जाल बुन कर उसमें घिरते जा रहे हैं।

हाल फिलहाल श्री अजमेरा के सूचना के अधिकार में दिए गए पत्रों से पूरे भोपाल के मुख्यालय के साथ ही सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में तूफान आया हुआ है। इस अंधड़ से यह भ्रष्ट ही सबसे ज्यादा बैचेन है। इसलिए इस धूर्त ने समय माया के शीर्षक को रद्द करने के व करवाने के लिए पत्र पंजीयन कार्यालय तक दौड़ लगाई है। वैसे ये मक्कार ये प्रयास सन 2000-01 में कर चुका है। जो निरर्थक साबित हो रहे है। सूचना के अधिकार में दिए गए इनके विभाग में सभी पत्रों के लिए ये समयमाया के मुख्य सम्पादक श्री अजमेरा को ही जिम्मेदार मानता है। जो अत्याधिक प्रसन्नता का विषय है कि लोग जागरुक होकर अधिकारों का प्रयोग करने लगे हैं। भले ही श्री अजमेरा को बदनाम

थे। उनको ये अहसास हो चुका था, इसलिए वो चुपचाप घूरती आँखों के बीच से पहले प्रदूषण मंडल के भ्रष्टाचार से प्रदूषित के परिसर से बाहर आए फिर लोगों को बाहर बुलाया, ताकि खुलकर दो-चार करते, परंतु कोई बाहर नहीं आया। यह बात पाठकों को समक्ष इसलिए रखी जा रही है कि उन्हें समझ आए कि ये जालसाज सफेदपोश अपराधी अपने कुकर्मों को दबाने के लिए किस तरह की नीचता के आदी हैं।

फर्जी नियुक्ति के संबंध में जानकारी चाहने पर कर दी रिपोर्ट

जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ म.प्र. की जिला इकाई के सचिव अजय शुक्ला ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल के लो.सू.अ से दिनांक 8/1/08 एवं 28/2/08 को सूचना के अधिकार के तहत विभाग से जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया था, आवेदक को सूचना न देनी पड़े तो मिश्रा ने अपने एक मील कर्मचारी जो ईसाई बन चुका है, जिसकी नियम विरुद्ध नियुक्ति ही इसलिए की गई थी, ताकि किसी को भी हरिजन एक्ट में फंसाकर धमकाया जा सके, इसकी सूचना मांगने पर इन धूर्तों ने उस पत्रकार के विरुद्ध हरिजन एक्ट में 4/3/08 को हरिजन थाने में रिपोर्ट लिखवा दी, पुलिस की गाड़ी भरकर उसे उठाने पहुंची, 25-30 पत्रकार इकट्ठे होकर आईजी के पास जाकर ज्ञापन देकर आए हैं। इस संबंध में क्षे.प्र. मिश्रा से बात की गई, तो कहना था, कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, ये यहां वर्षों से जमे कर्मचारी, वैज्ञानिकों और अधिकारियों की मुझे बदनाम करने की साजिश है।

से दूर-दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है।

म.प्र. वन विभाग को विश्व वनप्राणी संघ से हर वर्ष अमेरिकी डॉलर 2000 करोड़ मिलते थे, जिसका ये वनैले सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक से लेकर नीचे तक बैठे इंडियन फारेस्ट ईटिंग सर्विस (भारतीय वन खाओ सेवा) के अधिकारी ही ऊपर के ऊपर ही हजम कर जाते हैं।

दूसरा हर वर्ष विभाग में भा.वन खाओ सेवा के अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्र.मु. वन संरक्षक के अनुसार प्रदेश में 235 वन खाओ सेवा के अधिकारी हैं। इसके विपरीत वर्तमान में हर जिले में वन विभाग में 10 के आसपास भा.वन खाओ सेवा के अधिकारी विभिन्न शाखाओं में बैठाए गए हैं। जिनकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग 500 के आसपास है। जिसमें सामान्य वन उत्पादन, सामाजिक वानिकी, वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंध संचालक, विश्व खाद्य कार्यक्रम आदि तक में भा.वन सेवा के अधिकारी

में ओंकारेश्वर नहरों के दोनों तरफ मय प्रमाण देखे जा सकते है। जहां तक वन मंत्री जयंत मलैया, राज्यमंत्री विजय शाह का सवाल है तो एक को भ्रष्टाचार की वसूली से दूसरे को अय्याशी से ही फुर्सत ही नहीं है।

वन विभाग के विश्रामगृहों में महिला मित्रों के साथ शराब, शबाव के देर रात तक दौरों के समाचार इंदौर संभाग के वन विभाग में बैठे कर्मचारियों से मिलते हैं। फिर वन राज्यमंत्री को मांसाहारी भोजन ज्यादा पसंद है। इनकी अय्याशी, रंगरैलियों के बारे में समय माया ने अपने फरवरी के प्रथम सप्ताह के अंकों में वर्णित किया है। अर्थात इन दो पैर के सफेद और खाकी वर्दी वाले बनेलो की भूख तो इन बेचारे चार पैर वालों के दम पर ही हो रही है। फिर दोनों मंत्रियों का सिर आता चुनाव व खिसकती कुर्सी के भय से वसूली और राजसुख का अधिकतम उपयोग में लगा है, कल हो न हो, हो, तो सत्ता न हो, फिर क्या?

कमीशनखोरों को ...

शेष पेज ७ का

खाली पड़ी है उस पर विशाल भवन बनाया जा सकता है। इसके विपरीत चेतक चेम्बर के मालिकों को जो रुपए १ करोड़ वार्षिक का जो किराया पिछले १० से ज्यादा वर्षों से मिल रहा है। उसमें से वह बंदा रुपए २५ लाख आयुक्त मंत्री, सचिव तक बांटता है। इसलिए भ्रष्ट कुत्सित मानसिकता एक मंत्री बाबू गौर, सचिव सिंघल, आयुक्त पी.के. दास को इन बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, आखिर सरकारी भवन बन जाने के बाद इन मुखैरे श्वानों को हर वर्ष मोटा कमीशन कौन देगा, इसलिए यह कमीशन की गंदगी चाटने वालों की फौज में से अभी भी इस हादसे के बाद मौका, मुआयना कर सूं-सूं करते चले गए। बाहर कर्मचारियों से इन्हें कोई सहानुभूति नहीं थी जो इंदौर टावरिंग इंफनों में से मौत के मुंह से निकलकर आए थे। इन इँडियन एव्यूसिंग सर्विस के आयुक्त से लेकर सचिव, प्रधान सचिव और मुख्य सचिव को तो मजा ही तब आता है जब दो-चार की मौत हो जाती। मामला तूफानी आसमानी हो जाता, विधानसभा गूंजती।

इस बात को म.प्र. विधानसभा की विपक्ष की नेता श्रीमती जमुनादेवी को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठवाने के लिए। दिनांक १२-३-०८ को उनके विधानसभा स्थित कक्ष को दोपहर २.३० बजे फोन से बता दिया गया है। यह मामला विधानसभा में भी गूंजने की संभावना है। इससे संभवत: इस म.प्र. शासन के महत्वपूर्ण विभाग के कर्मचारियों को भयमुक्त वातावरण में कार्य करने का अवसर मिल सकेगा।

म.प्र. वाणिज्यकर भ्रष्टाचार का अंबार

सू.अ. में आवेदन लेने से इनकार

वृत्त १३-१४ एंटी इवेजन ब्यूरो अ और ब न इंकार, न स्वीकार

इंदौर के वाणिज्यकर विभाग के मुख्यालय से लेकर नीचे वृत्त कार्यालयों में सूचना के अधिकार के आवेदन में जानकारियां न देना पड़े, अपने कुकर्मों और भ्रष्टाचार की सच्चाइयां सामने न आए इसलिए आवेदक से आवेदन को ही स्वीकार नहीं लिए जाते, या फिर आवेदक को इन हरामखोर भ्रष्टों की फौज इस कमरे से उस कमरे में नचाती रहकर परेशान करने की आदी हो चुकी है।

इस संबंध में इस विभाग के एंटी इवेजन ब्यूरो में बैठे उपायुक्तों भरावी और श्रीवास्तव के एंटी इवेजन ब्यूरों के कार्यालय तो चेतक चेम्बर की पहली व आठवीं मंजिल पर हैं, परंतु ये दोनों उपायुक्त इन कक्षों में बैठने की अपेक्षा अपना सारा कारोबार अपने सहायक वाणिज्यकर अधिकारियों जिनक बारे में पूर्व में आदेश जारी कर उन्हें छापों में छापों की कार्यवाहियों से दूर रखने के लिए आदेशित किया गया था ही संभालते हैं। अर्थात सारे वैध-अवैध लेनदेन वसूली सहा. वा. कराधिकारी करे, हिस्सा भर मुख्यालय में बैठे उपायुक्तों तक पहुंचा दे, इस कार्यालय के दोनों अ और ब विंग में जो आवेदन अक्टूबर 07 में दिए गए थे इन धूर्तों ने लेने से मना कर दिया। स्वाभाविक था इनकी अपीलें लगाई गई। आयुक्त कार्यालय में इन अपीलों का निराकरण श्रीमती डामोर

को बलाए ताक में रखकर हर अपील में आवेदक को तो बुलाया परंतु उसके अंतर्गत कार्यरत हर अनावेदक को बचाने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाता। ताकि उसके मातहत अधिकारी के अवैधानिक/ गैरकानूनी या कानूनों को मजाक बनाकर उड़ा देने के संबंध में आवेदक के सामने उससे पूछताछ न की जा सके।

पिछले अंकों में बताया गया था कि कैसे महाभ्रष्ट मक्कार, धूर्त जालसाज वा.क.अ. एन.एन. झा ने आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर आवेदक को डराने धमकाने की कोशिश की थी। उसकी जब अपील की गई तो अपील अधिकारी ने वा.क.अ. एन.एन. झा और वा.क.ए.वृत्त क्रमांक 2 की श्रीमती सुलेखा जैन दोनों को ही बिना बुलाए 03.03. 08 को आवेदक को बुलाकर फिर वही बत्तमीजी दिखाई उन दोनों अधिकारियों को बुलाए बिना ही फिर आवेदक को ही इस जालसाज श्वान उपायुक्त एस.बी. सिंग ने परेशान किया। न ही इस मक्कार ने ये बताया कि इसने उन अपीलों पर क्या कार्यवाही की। उनके क्या जवाब प्राप्त हुए। इस प्रकार फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर अपनी जालसाज मानसिकता का परिचय दिया।

इस विभाग के अधिकारियों की जालसाजी का ये हरामखोर कदम-

उज्जैन संभागायुक्त का भी यही हाल

उज्जैन के ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग के संभागीय अधीक्षण यंत्री को सूचना के अधिकार में ऐसे ही एक पत्र धारा 6 (ए) व 6 (3) प्रथम व द्वितीय में दिया गया था। संभागीय अधीक्षण यंत्री ने तो उस पर तत्काल कार्यवाही कर दी थी, परंतु उज्जैन संभाग के जिसमें उज्जैन जिले, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच जिलों के कार्यपालन यंत्रियों ने उस पत्र को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। स्वाभाविक था कि जनता के धन को डकारने वाले इन हरामखोरों के विरुद्ध आवेदन का जवाब न देने के विरुद्ध अपील की जो संभागायुक्त उज्जैन को की गई। उसमें उज्जैन संभागायुक्त ने आवेदक को 23 फर. 08 को ही मात्र बुलवाया। उस धूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी ने भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दर किनार कर किसी भी अनावेदक को नहीं बुलवाया गया, ताकि भ्रष्टों से आवेदक के सामने पूछताछ कर उन्हें नीचा न दिखाया जाए। क्योंकि उनके भ्रष्टाचार में तो ये भी हिस्सेदार है। फिर जब यह बात वहां लिखकर दी गई तो पुनः अनावेदक को 3-3-08 को बुलवाया गया, ताकि ये धूर्त मक्कार आवेदकों को आतंकित कर सकें। इनके मातहत अधिकारियों को व उनके भ्रष्टाचारों को बचा सके।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार इन्हें ऐसी अपीलों के प्राप्त होते ही तत्काल अनावेदक/अनावेदकों से पूछताछ करनी चाहिए। समय सीमा में जवाब न देने पर, जवाब देने पर आवेदक को व्यक्तिगतत रूप से बुलाए जाने पर इन्हें यह दिखाना चाहिए कि इन्होंने उस अपील पर क्या कार्यवाही की उसके क्या जवाब प्राप्त हुए, परंतु कोई भी अधिकारी आवेदक को अनावेदक से किए गए पत्राचार के बारे में कुछ भी बताए बिना अपील अधिकारी मुख्यतः इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के जिलाधीश, आयुक्त के रूप में बैठे थे हरामखोरों की फौज अपने आप को खुदा समझते हुए अपनी तरह से आदेश पारित कर अधिकांशतः अपीलें खारिज कर देती है। इससे संबंधित भ्रष्ट गंदगी चाटने वाले शूकरों की फौज का वजन बढ जाता है। वो ऐसी अपीलों को आवेदनों को जवाब देने की अपेक्षा रद्दी की टोकरी में डाल पुनः भ्रष्टाचार की गंदगी में लौट लगाने लगते हैं।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार आवेदक की अपील प्राप्त होने पर अनावेदकों से पूछताछ करना चाहिए, संतुष्ट होने पर आवेदक व अनावेदक को आमने-सामने बैठाकर निर्णय किया जाना चाहिए, पर ये महाधूर्त

बैंकर्स काटेंगे चांदी, कृषक फिर भी लंगोटी में

बैंकर्स की जालसाजियों पर सफेदा

किसानों की ऋण माफी के नाम पर रुपए 60,000/- करोड़ के जो ऋण माफ करने की बात कही गई है, पूरा किसानों का कर्ज रुपए 20000 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा। रुपए 60000 करोड़ की घोषणा की आंकडों की बाजीगरी थी। दूसरा सचमुच जिस कर्ज जो कि बैंकों और सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज को ये माफ करेंगे, उससे क्या छोटी जोत जो लघु और सीमांत कृषक जिसके पास 1 एकड़ से 10-15 एकड़ तक कृषि भूमि है क्या वास्तविकता में उनको इस कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। कदापि नहीं, क्योंकि बैंक सरकारी हो या सहकारी हो, यहां पर इतने हरामखोरों, जालसाजों, भ्रष्टों की फौज बैठी है कि वो छोटे किसानों को कर्ज देने के नाम पर चक्कर लगवा-लगवा कर प्राण लेने लगती है, इसलिए वो बेचारे वहां के स्थानीय साहूकारों से कर्जा लेकर ही काम चलाते हैं। जो उनके अड़े-भिड़े में काम आता है।

चंद कुछ कागजों पर उसकी जमीन व अन्य स्थाई सम्पत्तियों के साथ बीबी, बच्चों को भी गिरवी रखकर ऋण दे देता है, उसको 2 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत मासिक ब्याज पर उन गिद्ध रूपी महाजनों से ही कर्ज लेना पड़ता है। जिसके चंगुल से वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी तक मुक्ति नहीं पा पाता। उस कर्ज की माफी की व्यवस्था की जाए तो वास्तविकता में उसकी कर्ज मुक्ति हो।

अब जब किसानों को जो 10-15 एकड़ से लेकर ज्यादा 100-200 एकड़ जमीनों को मालिक होंगे जिनकी अपनी कारें और गाड़ी होंगी जिन्होंने कृषि ऋणों को अपने व्यक्तिगत व व्यावसायिक उपयोग में लिया होगा, उनके भी कृषि ऋण माफ हो जाएंगे। वो असली मलाई चाटेंगे, साथ ही मलाई चाटने वालों में होंगे बैंक कर्मचारी और अधिकारी जो कृषि ऋण के नाम पर अपने कुकर्मों, रिश्वत खोरी और भ्रष्टाचार को न केवल सुकर्मों में परिवर्तित कर लेंगे, वरन् जिन्हें, उन्होंने कर्ज दिया ही नहीं उन कृषकों से झूठे ही अंगूठे और हस्ताक्षर ऋण खातों में दिखाकर पैसे स्वयं ही डकार गए थे वो सब काले-पीले कुकर्म उनके आसानी से दबा दिए जाएंगे। साथ ही पुरानी तारीखों में पड़े कृषकों के कर्जों को स्वीकृत कर यहां कृषि ऋण खातों में नामे डालकर उनके बचत खातों में जमाकर भी बैंकर्स स्वयं ही हजारों करोड़ डकार लेंगे, मार्च के खातों को बंद करने से पहले ही। इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं।

बेशक इस कर्ज माफी की घोषणा होते ही 29 फरवरी 08 की तारीख

गए थे इन धूर्तों ने लेने से मना कर दिया। स्वाभाविक था इनकी अपीलें लगाई गई। आयुक्त कार्यालय में इन अपीलों का निराकरण श्रीमती डामोर ने आयुक्त के आदेश पर दिए, परंतु जालसाजों ने अपने मातहतों को बचाने के लिए फिर भी उन्हें बचाते हुए शब्दों का जाल अवश्य बिखेरा। इसके विपरीत अपील अधिकारी ने आवेदक को चाही गई जानकारी देने के लिए आदेशित नहीं किया।

यहां बैठे अधिकारियों, आयुक्त, उपायुक्तों, सहा. आयुक्तों, वाणिज्यकर अधिकारियों की भ्रष्ट मक्कार फौज भ्रष्टाचार में इतने गहरी धंसी हुई है कि उन्हें अपने मातहतों के सारे कुकर्म, दुष्कर्मों को खुलने से बचाने के लिए कानूनों की तोड़मरोड़ कर व्याख्या करना इन धूर्तों का शगल बन चुका है। इंदौर के उपायुक्त एस.वी. सिंग संभाग-1 को दी गई हर अपील में इस धूर्त ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर अपनी जालसाज मानसिकता का परिचय दिया।

इस विभाग के अधिकारियों की जालसाजी का ये हरामखोर कदम-कदम सबूत छोड़ते हैं। आवेदक को सुनवाई के समय पत्र देते समय ये निकम्मे यह तक नहीं लिखते कि किस प्रकरण में किस आवेदक के विरुद्ध सुनवाई के लिए बुलवाया जा रहा है। सबको ये जालसाज अपना व्यापारी ही समझते हैं। जहां बैठे वकील रूपी दलालों से ये सौदेबाजी कर धन कमाते हैं। वैसे ही सूचना के अधिकार में दिए गए आवेदनों में ये आवेदक के भी अपने व्यापारियों की तरह तोलकर उनका वजन हल्का मान अपना वजन भारी होने का अहसास करवाते हैं। सारे कानून इन हरामखोरों की बपौती है। ये जैसे चाहे उसकी व्याख्या करें, जैसे चाहें तोडे, मरोड़ें और आम जनता को अपनी भाषा में समझा दें।

प्रेसकर्मी और पत्रकार

शेष पेज ८ का

वेतनमान लागू करवाने की जिम्मेदारी के रूप में जब श्रम विभाग की भूमिका का प्रश्न उठा तो उपायुक्त पांडे सहायुक्त श्रीमती सुषमा ठाकुर ने अपनी बहादूरी की डींगे हांकी पर सच इसके विपरीत यह भी था और है कि वे कितनी बार वर्ष में कितनी और कौन सी प्रेस में घुसकर कर्मचारियों से पूछताछ कर पाए। श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक से लेकर आयुक्त तक डींगे कितनी भी हांके-फांके, निष्कर्ष यह है कि श्रम विाग के अदने से निरीक्षक से लेकर श्रमायुक्त की भी हिम्मत नहीं कि वो किसी प्रेस परिसर में घुसकर पूछताछ कर सकें, क्योंकि ये स्वयं इतने भ्रष्ट हैं कि अगले दिन ही इनकी कहानी समाचार पत्रों में होगी। फिर कौन श्रमाधिकारी, निरीक्षक से लेकर सहायकायुक्त, उपायुक्त, आयुक्त घुसकर आ बैल मुझे मार करेगा।

जहां तक इंदौर का सवाल है तो यहां का उपायुक्त पाठक तो पूरे शहर में दैनिक समाचार पत्रों की प्रेस को छोडकर सभी नियोक्ताओं से श्रम कानूनों के उल्लंघन में और उल्लंघन करते रहने की छूट की मासिक वसूली करता है तो एलके पाठक की क्या मजाल है कि वो प्रेस को छेड़ कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। इस संबंध में श्री अजमेरा ने सुझाव दिया कि अगर श्रम विभाग वास्तविकता में कर्मचारियों के बारे में गंभीर है तो शाम 4बजे, रात 12 बजे, सुबह 4 बजे प्रेस परिसरों में घुसकर देखे कि कहां कितने कर्मचारी, किस रूप में कार्यरत हैं। उन्हें क्या वेतन मिल रहा है, यहां जांच भी हर दो तीन माह में अचानक की जाए तो फिर उनके स्थायीकरण की बात, वेतन भत्तों, बीमा, चिकित्सा लाभ, छुट्टियों, भविष्यनिधि अंशदान, पेंशन, वेतनमान की बातें सार्थक हो सकती है। अन्यथा निरर्थक है। यह तथ्य श्री साहनी को पसंद भी आया ताकि कर्मचारियों का वास्तविकता में भला हो सके।

गंदगी में लौट लगाने लगते हैं।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार आवेदक की अपील प्राप्त होने पर अनावेदकों से पूछताछ करना चाहिए, संतुष्ट होने पर आवेदक व अनावेदक को आमने-सामने बैठाकर निर्णय किया जाना चाहिए, पर ये महाधूर्त आईएएस, मात्र आवेदक को बुलाकर अपने पद का वजन बताकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकांश सूचना अधिकार की अपीलों में इनकी गर्दन फंसी होने के कारण खारिज कर दी जाती है। यही हाल इंदौर के धूर्त संभागायुक्त बी.पी. सिंग ने भी ग्रा.यां.वि. की अपील में किया था। कानून इन हरामखोरों के पर्स का विजिटिंग कार्ड हो।

दबा दिए जाएंगे। साथ ही पुरानी तारीखों में पड़े कृषकों के कर्जों को स्वीकृत कर यहां कृषि ऋण खातों में नामे डालकर उनके बचत खातों में जमाकर भी बैंकर्स स्वयं ही हजारों करोड़ डकार लेंगे, मार्च के खातों को बंद करने से पहले ही। इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं।

बेशक इस कर्ज माफी की घोषणा होते ही 29 फरवरी 08 की तारीख में ही हजारों करोड़ रु. की कृषि ऋण स्वीकृत किए जाकर बैंकर्स कृषकों, ग्रामीणों के नाम से डकार जाएंगे, आधे-आधे में अर्थात गरीब व छोटी जोत वाला कृषक वहीं की वहीं लंगोटी लगाए साहूकारों और महाजनों की सेवा में जी-हजूरी करता रहेगा। जालसाज मलाई चाटेंगे।

रुपए २१५० करोड़ की निविदाएं आनन-फानन कमाई के लिए

नघाविप्रा में 322.5 रु. करोड़ चुनावी चंदे के लिए अग्रिम

काम कैसा भी हो, १ वर्ष में पूरा भुगतान ठेकेदारों को, अग्रिम भी वापस

भोपाल। भाजपा को आसन्न चुनावों के लिए धन चाहिए, इसलिए अब वह येनकेन प्रकारेण जनता के धन को डकारने के लिए बहुविधि हथकंडे अपनाने व धन एकत्रिकरण पर ध्यान केंद्रीत कर रही है।

हाल ही में म.प्र. की बहुउद्देशीय नर्मदाघाटी परियोजना में इंदिरा सागर, बारगी, ओंकारेश्वर आदि नहरों को निर्माण के लिए म.प्र. की भाजपा सरकार ने रुपए 2150 करोड़ की निविदाएं बुलाई है।

इन निविदाओं में दी गई शर्तें पूर्णतः आसन्न चुनावों के मद्देनजर निर्धारित की गई है, ताकि ये सीधा रु. 322 करोड़ 50 लाख सीधे ठेकेदारों को देने के बहाने डकार सकें। इसकी शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को 10% अग्रिम कार्य शुरू करने व 5% अग्रिम चलित पूंजी के रूप में दे दिया जाएगा। हास्यास्पद पहलू यह है कि ये ठेके पूर्व से भ्रष्ट, कामचोर, जालसाल ठेकेदारों जो आधे अधूरे काम छोड़े बैठे हैं। इंदिरा सागर, नहरों में जैसे बिहानी, जलगांव, सोमदत्त, कर्णसिंग जैसों की भी दे दिए गए हैं। अब स्वयं इंजीनियर्स जो वहां संभागों और संभागों को संभाल रहे हैं। स्वयं परेशानी में है कि पूर्व का कार्य अभी अधूरा है और पुनः नए ठेकों में भी इन्होंने हाथ मार लिए हैं।

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण सच्चे अर्थों में ऐसे हरामखोरों का समूह है जहां प्राक्कलन से लेकर संरचना डिजाइन और निर्माण के अंतिम दौर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसके तकनीकी बारीकियों में जाकर देखें तो बांध निर्माण से लेकर हर कदम ये हर शासकीय अधिकारी, मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह से लेकर सुंदरलाल पटवा, दिग्गी दानव, उमा भारती, बाबू गौर, शिव चौहान 100 ली दूध देने वाली गाय है। इसलिए हर मंत्री, संत्री से लेकर सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न.घा.वि. प्रा. सदस्यों से लेकर इंजीनियरों, जिसमें मुख्य अभियंताओं से लेकर सुपर वाइजर और बैठे बाबुओं तक की जेबों से लेकर बैंक खातों को पिछले 30वर्षों से सींच रही है।

इस न.घा. वि.प्रा. के 29 बड़े बांधों, 250 से ज्यादा छोटे बांधों में सर्वेक्षण से लेकर निर्माण तक अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, हो चुका है और होता रहेगा। ऐसा नहीं कि केवल न.घा.वि.प्रा. वहन संबंधित जिले के जिलाधीशों ने भी जिसमें धार, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, जबलपुर, नरसिंगपुर,

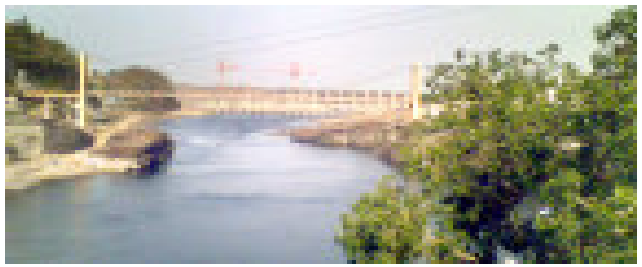

सिवनी, देवास, खरगोन, भूअर्जन आवंटन आदि में दोनों हाथों से झूठे फर्जी मुआवजों से भारी भ्रष्टाचार किया।

अभी भी जो रुपए 2150 करोड़ के ठेकों की निविदाएं बुलाई गई थी, स्वयं इंजीनियरों के अनुसार सरकार का 70प्रतिशत पैसा डूब में जाएगा। ठेकों की शर्तों के अनुसार ठेकों के कार्य की जमानती राशि के रूप में ली जा रही है। अनेस्टमनी भी ठेकेदारों का कार्य पूरा हो न हो एक वर्ष बाद वापस कर दी जाएगी। 15% (10+5) अग्रिम कार्यादिश देने के साथ ही ठेकेदारों को दे दिया जाएगा। यही 15% अर्थात रुपए 322.5 करोड़ के ठेकेदारों के अग्रिम के बहाने मुख्यमंत्री शिव चौहान, न.घा.वि.प्र. मंत्री नागेंद्रसिंग, उपाध्यक्ष प्रदीप भार्गव, सदस्य व्ही.के. भाटिया, सदस्य वित्त रमेशचंद्र से लेकर संबंधित मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री व संभागीय कार्यपालन अभियंता तक कार्यादेश देने में ही डकारेंगे बेशक शेरू हिस्सा मुख्यमंत्री, न.घा.वि.प्रा. मंत्री नागेंद्रसिंग का होगा, जिसका लगभग 50% तक भाजपा के आने वाले चुनावी फंड में ही जाएगा।

जिस तरह से वृहत ठेके देकर कार्य करवाया व हो रहा है, पूरी नर्मदा घाटी के इंदौर संभाग में बनने वाली इंदिरा सागर बांध की नहरें, ओंकारेश्वर की दायीं तट नहर में चल रहे कार्य को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि भविष्य क्या होगा, अकेले ओंकारेश्वर की दायीं तट नहर परियोजना में जो रुपए 178 अब बढ़कर रुपए 203 करोड़ का जो कार्य सोमदत्त ठेकेदार उसका कांट्रेक्टर कर्णसिंग जिस तरह कार्य मापदंडों को बलाए ताक रखकर करवा रहे हैं,

शेष पेज ३ पर

म.बा.वि. में भ्रष्टाचार से हो रहा अधिकारियों, कार्यकर्ताओं का विकास

महिलाओं व बाल विकास में हो रहे भ्रष्टाचार का तांडव

अधिकांश आंगनवाडियों में रजिस्टर में दिखाए जा रहे बच्चे ही नहीं

इंदौर। महिला बाल विकास विभाग में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा खुलकर हर योजना 60 से 70 प्रतिशत तक धन झूठे व्हाउचरों, झूठी लॉग बुक में प्रविष्टियों, आंगनवाड़ियों में आपूर्ति किए जाने वाले पोषण आहार के झूठे व्हाउचरों के साथ ही इंदौर जिले, ब्लाकों के साथ ही यही हाल उज्जैन नगर और विकासखंडों में चल रही आंगनवाड़ियों में हो रहा है। जितने महिला व बच्चे आंगनवाड़ियों के रजिस्टर में दिखाए जा रहे हैं 95 प्रतिशत में उतने बच्चे ही नहीं है, फिर भी झूठे फर्जी नामों को भरकर उनके पोषण आहार व अन्य योजनाओं का धन वहां बैठे अधिकारियों को धन बांटकर खुलकर डकारा जा रहा है। इंदौर जिले के सांवेर ब्लाक में बैठ धूर्त मधुमति सिरोले सरस्वती स्व. सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती राठौर से तगड़ा धन वसूल कर रही है। ऐसे ही श्रीमती सोनी के स्व. सहायता समूह से जमकर वसूली की जा रही है। जिला अधिकारी श्रीमती मुंजला तिवारी को श्रीमती मधुमति से रुपए 30,000 प्रतिमाह की मोटी धनराशि हर महीने वसूली देती है। यही हाल महू ब्लाक, देपालपुर ब्लाक का भी है। श्रीमती मंजुला तिवारी ने

है जो कि कानूनी रूप से अवैध है। सांवेर में परियोजना अधिकारी को हर माह टैक्सी किराये से लेनी चाहिए, परंतु ये बंदी अपनी कार को शासकीय कार्यों में टैक्सी के रूप में लगाकर स्वयं बिल वसूली कर अपने खर्चों को शासन के खाते से वसूल रही हैं।

पूरे प्रदेश के महिला बाल विकास में बच्चों और महिलाओं के विकास के नाम पर विशुद्ध लूट-पाट का तांडव ही चल रहा है। अधिकांश कागजी कार्यवाहियां ही हो रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं से लेकर ऊपरमंत्री स्तर तक बैठी मक्कार, जालसाज फौज 50 प्रतिशत से ज्यादा धन से स्वयं के विकास पर खर्च कर रही है। इसके विपरीत शहरीय गरीब बस्तियों और ग्रामीण बस्तियों में रहने वाली गरीब महिला और बच्चों की स्थिति दयनीय ही बनी हुई है। कुपोषण से गरीब महिलाएं बच्चे न केवल शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर और बीमार बन रहे हैं, जबकि इनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चों के नाम इस विभाग के सभी शहरों की गरीब बस्तियों व ग्रामीण महिला बाल विकास के खातों में चढ़े होकर इनके नाम से सारे शासकीय धन को वहां बैठी महिला अधिकारी सांडों की भांति खुलकर चर रहे होती हैं। यदि इनकी बारीकी से जांच की जाए तो अकेले इंदौर, उज्जैन संभाग में एक वर्ष में रुपए 50 करोड़ से 1 अरब तक का धन डकारने के जाली दस्तावेज मिलेंगे। ऐसे विकास हो रहा है महिला और बच्चों का अगले अंकों में पढ़िये अनेको कई सच्चाइयां...।.

चेतक चेम्बर के वाणिज्यकर विभाग में आग

कमीशनखोरों को भीषण हादसे का इंतजार

भ्रष्टाचार, मूल कारण है अपराधों में लगातार वृद्धि

वैश्यावृत्ति में जुटी छात्राएं भावीयां भी कर रही ड्रग कैरियर का कार्य

पूरे म.प्र. के हर जिले में चोरी, डकैती, हत्याएं, सिमी का बढ़ती गतिविधियां, आतंकवाद की धमकियां नशे का फैलता बढ़ते रहने के मूल कारणों में पुलिस विभाग में चारों तरफ बढ़ता भ्रष्टाचार ही है। अकेले इंदौर, उज्जैन संभागों के पुलिस विभाग के छह महीने के अपराधों के ग्राफ में लगातार वृद्धि है इस बात के स्पष्ट प्रमाण है। वाहनों की चोरियां, सूने पड़े बंद मकानों, फ्लेटों, दुकानों में रात में शटर उचका कर की जा रही लगातार बढती रही चोरियों को पकड़ने में पुलिस बिलकुल निकम्मी साबित हो रही है।

अब आए दिन अपहरण की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। इसके संबंध में जब कुछ इंदौर, उज्जैन के थानों में गहराई से छानबीन की गई तो जो तथ्य सामने आए वो बेहद निराशाजनक थे। अधिकांश थानों में बैठाए गए निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों, सहनिरीक्षकों, हैड साहब का ध्यान अधिकांश समय वसूली पर ही लगा देखा गया, ये वसूलियां तो क्षेत्र के अपराधियों, कबाड़ियों, सटोरियों, जुआरियों, अवैध नशे का व्यापार करने, अवैध शराब बेचने वालों, जिम, ब्यूटी पार्लरों के नाम पर चल रहे वैश्यावृत्ति के अड्डों, क्षेत्र में घरेलू महिलाओं का लिबास ओढ़े मोबाइलों पर चलने वाली वैश्याओं से वसूली और उनका साथ शारीरिक मौज मस्ती का आनंद लेने में लिप्त पाए गए। कालेज की छात्राओं, होस्टलों में रहने वाली लड़कियों के साथ ही घरेलू महिलाएं भी जो अधिकांशत: एकल परिवारों में रहती है। कुछ मामले संयुक्त परिवारों की महिलाओं के भी पाए गए। पतियों के घर से काम, धंधे, नौकरी पर जाने ही वे न केवल धन के बंदे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, अगर चंगुल में फंस ही गई उसको भी अपने बदन से खेलने का मौका देकर मुंह पर ताला डाल देती है। इस प्रकार ये अपराधों की दुनिया अपने-अपने नए आयाम स्थापित करती हुई पूरे पुलिस विभाग का कृष्ण मुखकर समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रही हैं।

इंदौर में ये पलासिया, विजय नगर, खजराना, साऊथ तुकोगंज, एमजीरोड, भंवरकुआ जैसे सभी थानों में यह सब खुलकर हो रहा है। इसके जिलों के भी यही हाल है। बेशक इंदौर व्यावसायिक राजधानी होने के कारण ड्रग्स अवैध कारोबार, वैश्यावृत्ति के नाम पर म.प्र. में सबसे आगे हैं। सिमी के धन का आधार ही ड्रग्स रहा है। उज्जैन जिले में चूंकि ये धार्मिक तीर्थ नगरी होने के साथ रेलवे का भी जंक्शन है इसलिए नशे के अधिकांश कारोबारियों और सिमी के अड्डे के रूप में पूरे प्रदेशभर में कुख्यात हो चुका है।

ड्रग्स के कारोबार में महाकाल थाना क्षेत्र सबसे ज्यादा आगे है, यहां पर आने वाले यात्रियों, रहवासियों से साधुओं, संतों को अफीम,चरस, गांजा, भांग के शौकीनों की संख्या ज्यादा है। फिर नीमच, मंदसौर से आगे वाले नशे की ड्रग्स की खेपों का बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में रोज की खप जाता है। जिसमें यात्रियों के साथ ही रहवासियों की दैनिक आवश्यकता का हिस्सा होने के कारण आपूर्तिकर्ताओं में एजेंटों के रूप में अब छात्राओं और भावीयों जो वैश्यावृत्ति से धन कमाने के साथ ही ड्रग्स के अवैध कारोबार में भी गल तक धंसी फंसी है। उज्जैन जो सिमी का गढ रहा है, ऐसी भावीयों, छात्राओं को वैश्यावृत्ति करते, करवाते समय मोटा धन देकर पहले फांसता है। ब्ला

अर्दली कर पुलिस की पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां चलाकर अपने स्वाभिमान को बचाते हुए दिन गुजारने पर मजबूर हैं।

हर पुलिस स्टेशन पर दो-चार ऐसे कांस्टेबलों को रखने की व्यवस्था रहती है जो उस थाना क्षेत्र के अपराधियों पर न केवल नजर रखते हैं, वरन उस थाना क्षेत्र में चल रही गतिविधियों पर भी नजर रखकर पुलिस की साख को बचाए रखने साथ ही अपराधियों को पहचनना, अपराध क्षेत्रों पर नजर रखना, कौन कितने बजे आता-जाता है ये सब तुरंत ही अपराध घटने, होने की दशा में कौन, किस चीज में मास्टरी और कारगुजारी करता है का ध्यान रखकर तुरंत अपराधियों की घेराबंदी करते हैं। ऐसे ही कुछ कांस्टेबलं से जो विभिन्न थानों में पदस्थ थे से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि अब ऐसे काम पर उन कांस्टेबलों को लगाया जाता है जिन्हें क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं होती,जिन्हें वसूली के लिए बिना बताए गंतव्य पर भेज कर महीना, हफ्ता वसूली का करवाई जात है जो साहब के घव की सब्जी लाने, आटा पिसवाने और कुत्तों को घुमाने का कार्य कर सकते हैं। अब अगर कोई खुफिया जानकारी पुलिस के सहयोगी आम जनता या आम आदमी पहुंचा भी देता है तो उल्टे ही अपराधियों को जानकारी देकर अपराधियों, वैश्याओं, सटोरियों, ड्रग एजेंट्स, जुआरियों, कबाड़ियों जो गाड़ी तोड़कर बेचने का काम करते हैं। इंदौर के ही नए बाजार के कबाड़ी जिनके बारे में चर्चा है रुपए ३०,००० /- प्रति माह थानों में पहुंचाते हैं। सुरक्षित स्थानों पर भागने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसे ब्यूटी पार्लरों, जिम सेंटरों, जिनमें खुलकर वैश्यावृत्ति की व करवाई

से रुपए 30,000 प्रतिमाह की मोटी धनराशि हर महीने वसूली देती है। यही हाल महू ब्लाक, देपालपुर ब्लाक का भी है। श्रीमती मंजुला तिवारी ने जो रुपए 70 लाख से ज्यादा का बंगला बालाजी बिहार में बनवाया है उसकी भी जानकारी शासन को नहीं दी गई है। निःसंदेह लोकायुक्त को चाहिए कि उस बंगले और इंदौर में श्रीमती मंजूला तिवारी के विभिन्न बैंकों में लाखों रुपए सावधि जमा कहां से आई की जांच करें, इन्हें सीखचों के पीछे पहुंचाएं।

सभी ब्लाकों में वहां बैठी महिला एवं बाल विकास अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों में जमकर वसूली की जा रही है। ये समाचार न केवल इंदौर संभाग के इंदौर जिले के सभी विकासखंडों, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी के साथ ही उज्जैन संभाग के उज्जैन जिले के साथ ही देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच के भी हैं। 95 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चूंकि धन खर्च करके आंगनवाड़ी प्राप्त करते हैं। तो स्वाभाविक है कि खुलकर झुठे, फर्जी बच्चों की प्रविष्टियां दिखाकर उनके नाम से उनके पोषण आहार को बाजार में बेचकर मोटी रकम डकार जाते हैं। कुछ हिस्सा वहां के विकासखंडों की महिला बाल विकास अधिकारी को खिलाकर सब रफा-दफा कर दिया जाता है। फिर जहां महिलाएं जो अधिकारियों के रूप में बैठी हैं यदि उनके ऊपर पुरुष अधिकारी बैठे हैं। यदि उनकी सेवा तन, मन से कर दी जाती है तो फिर कौन सा पुरुष अधिकारी उसकी तन,मन,धन की सेवा के विपरीत उनकी जालसाजियों के ऊपर हस्ताक्षर कर सब काले-पीले को सफेद करने को मुहर नहीं लगाएगा। सांवेर ब्लाक में तो श्रीमती मधुमति के साथ उनका पति भी वहीं कार्यरत है। जिसकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली भी लिखती

कमीशनखोरी का भीषण हादसे का इंतजार

इंदौर। म.प्र. का वाणिज्यकर विभाग म.प्र. शासन को रुपए ७००० करोड़ की आय दे रहा है। इसके विपरीत इसके इंदौर मुख्यालय और अन्य रिभागों का अपना भवन नहीं है। जहां मुख्यालय का आयुक्त कार्यालय म.प्र. के न्याय विभाग के भवन में कब्जा जमाए बैठा है। वहीं इसके १५ वाणिज्य कर वृत्त उपायुक्तों के कार्यालय भी किराए के खतरनाक चेतक चेम्बर में मात्र किराए के रुपए १० लाख से ज्यादा के कमीशन डकारने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें सोमवार ११.४५ पर तृतीय तल जिसे प्रथम मंजिल बोला जाता है में केबल में चिंगारियां फूटना शुरू हुई जो ४थी, ५वीं, ६वीं, ७वीं, ८वीं, ९वीं मंजिल जिसे दूसरी, तीसरी ४थी, ५वीं, ६ठवीं, ७वीं मंजिल कहा जाता है तक पहुंच गई। पानी के सारे नकली पम्प स्वाभाविक थे नकली थे तो केबल दिखाने के लिए थे, बंद पड़े थे। दोनों तरफ के दरवाजों पर भी ताले लगे थे। २०० से ज्यादा कर्मचारियों ने दोनों कोनों के ताले और शटर तोड़कर निकलने की कोशिश की, कर्मचारी पाईप से उतरने के चक्कर में हाथ, पैर भी तुड़वा बैठा। बाद में फायर बिग्रेड ने पहुंचकर करीब २ बजे आग पर काबू पाया। सारे कर्मचारियों ने तब ही से कलम बंद हड़ताल कर दी, बाहर तब से धरने पर बैठे हैं। समय माया लगातार ३ वर्ष से यह खबर छाप रहा था कि इस भवन में दो हादसे पहले भी हो चुके हैं और हादसे होने की संभावा है। जबकि अफीम गोदाम की जमीन **शेष पेज ५ पर**

घरेलू महिलाएं भी जो अधिकांशत: एकल परिवारों में रहती है। कुछ मामले संयुक्त परिवारों की महिलाओं के भी पाए गए। पतियों के घर से काम, धंधे, नौकरी पर जाते ही वे न केवल धन कमाने और मौज मस्ती के लिए घरों से निकल कर होटलों, ढाबों, खाली पड़े फ्लेटों, मकानों, छोटे कार्यालयों की तरफ अपने दोपहिया वाहनों से निकल जाती है। ये १२ बजे से लेकर शाम को पति के ७-८ बजे घर पहुंचने के पहले ८-१० ग्राहकों को जो अधिकांश अपराधी किस्म के हैं अवैध नशे, ड्रग्स के कारोबार, सफेदपोश सटोरियों जुआरियों से ही अपनी कद काठी के हिसाब से वसूली कर घर लौट कर आ जाती है। साथ में नशे की पुड़िया और पैकेट लाकर दूसरे यारों एजेंटो को देकर वैश्यावृत्ति के साथ ही नशे के कारोबार से भी धन कमा रही है। इन अपराधियों को ऐसी छात्राओं और भावियों से भोज के साथ ही ये धंधा सुरक्षित, सटिक और फायदेमंद अचूक लगता है। दूसरा ये भावीया दिन में खाली रहकर इस वैश्यावृत्ति के साथ ही ड्रग के इस धंधे को बिना किसी शक सुबह के सटीकता से अंजाम देती रहती हैं, जिससे आम आदमी तो दूर ये पॉश कालोनियों और सघन बस्ती में रहने वाली इन घरेलू महिलाओं का ढोंग रचने वाली भावीयों पर पुलिस ड्रग्स के अवैध कारोबार में भी गल तक धंसी फंसी है। उज्जैन जो सिमी का गढ रहा है, ऐसी भावीयों, छात्राओं को वैश्यावृत्ति करते, करवाते समय मोटा धन देकर पहले फांसता है। ब्ल्यू फिल्म बनाकर धन के आधार पर उन्हें अपने नशे के व्यापार में शामिल कर अपना सुरक्षित तरीके से इनके सहारे व्यापार करवा रहा है। सिमी को मिलने वाला धन ड्रग्स के माध्यम से भी मिलता है। ये भावीयां उज्जैन के देवास गेट की होटलों, नानाखेड़ा की होटलों में वैश्यावृत्ति करने के साथ ड्रग्स केरियर के रूप में ही महीने भर में रुपए ५०००० से लेकर लाखों तक कमा रही हैं।

महाकाल थाने की पुलिस को ये रिपोर्ट मिलती रहती है, उसे तो वसूली से काम है। आसी ही एक एजेंट भावी के नम्बर जो उस भावी से इस प्रकार की वैश्यावृत्ति और ड्रग्स के कारोबार से संसंबधित सौंपे जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। इसके विपरीत हर थाने में बैठने वाले खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाले ईमानदारों, कांस्टेबलों की पुलिस के अधिकारियों का सहयोग न मिलने और अधिकारियों की भ्रष्ट वसूली और मौज मस्ती की मानसिकता के कारण ऐसे अधिकांश कांस्टेबल अब चुपचाप लाईन अटैच होकर बंगलों में बारे में चर्चा है रुपए ३०,००० /- प्रति माह थानों में पहुंचाते हैं। सुरक्षित स्थानों पर भागने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसे ब्यूटी पार्लरों, जिम सेंटरों, जिनमें खुलकर वैश्यावृत्ति की व करवाई जा रही है। चूंकि स्वयं पुलिस अधिकारी यौनानंद में लिप्त हैं। ऐसीहोटलों, क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, जिम सेंटरों को सूचित कर दिया जाता है। ऐसे ही एक मामले में २८-२-०८ को हमारे उज्जैन प्रतिनिधि ने एक धंधा करने वाली भावी जो ड्रग केरियर का काम भी करती है सायं ३.३० बजे होटल श्रद्धा नानाखेड़ा में जाते देखा। बाहर चार पहिये की गाड़ी खड़ी थी। महिला थाने की टी.आई. को सूचित किया। जबकि वो प्रतिनिधि भी पीछे-पीछे घुसा, भावी सीधे ऊपर की मंजिल में गई। करीब एक घंटे तक पुलिस का इंतजार किया, परंतु वहां कोई नहीं पहुंचा। बाद में जान बचाकर उस प्रतिनिधि को वहां से भागना पड़ा। ये हालात इस प्रदेश के हर बड़े शहर की पुलिस कमान के हैं। इन्हें अपने भ्रष्टाचार, वसूली मौज-मस्ती से ही फुर्सत नहीं मिलती। स्वाभाविख है पुलिस सुस्त तो अपराधी चुस्त-दुरुस्त रहकर अपनी कारगुजारी दिखाएंगे। सत्ताधीशों की पकड़ ही नहीं बन पा रही है।प्रशासन पर लगाम कसने और अपराधों पर अंकुश लगाने की तो आम जनता को हैरान परेशान होना और लुटना ही पड़ेगा।

भविष्य में संचार...

शेष पेज ८ का

युद्ध में झोंके और बिना एक भी सैनिक मरे और मरवाये बिना भी आसानी से जंग जीतने में एक मिसाइल से ही शत्रु राष्ट्रों के उपग्रह, अंतरिक्ष में बिना कुछ बोले चाले नष्ट कर भी शत्रुओं को पंगु बनाया जा सकता है।

वर्तमान में अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए अमेरिका, रूस और चीन के पास ऐसे उपग्रह हैं जो आंतरिक्ष में जाकर ऐसे उपग्रहों को ढूंढकर नष्ट कर सकते हैं। धरती से अंतरिक्ष में मिसाइलों से उपग्रहों का नष्ट करने का प्रदर्शन कर जिस स्टार्सवार का अमेरिका ने अग्रिम चेतावनी दी है उससे न केवल विश्व के सभी राष्ट्रों को संचार उपग्रहों पर निर्भरता को शीघ्रता से कम तो करना ही होगा, साथ ही उपग्रहों की संचार प्रणाली के नष्ट होने पर सामानांतर या वैकल्पिक व्यवस्था क्या और कैसे होगी की व्यवस्थाएं जमाने की चेतावनी भी दे दी है।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से लेकर संचार मंत्रालय, वैमानिकी, रेलवे, बैंकिंग व प्रशासनिक व्यवस्थाओं को इस दिशा में गंभीर चिंतन और वैकल्पिक व समानांतर व्यवस्था की भी तैयारी शीघ्र ही करना होगी, अन्यथा शत्रु चाहे वो फिर अमेरिका हो या चीन हमारी इस कमजोरी का तत्परता से फायदा उठाकर हमारी अर्थव्यवस्था, शासकीय प्रबंधन व्यवस्था वैज्ञानिकी, रेल, जल यातायात व्यवस्था, दूरसंचार में फोन, सेलफोन, टीवी, रेडियो, ब्राडकास्टिंग आदि को चंद घंटों में ही नष्ट कर पूरे राष्ट्र को पंगु बनाने में कसर नहीं छोड़ेगें। अमेरिका ने जमीन से मिसाइल मारकर उपग्रह नष्ट करने के अपने इस कारनामें से अपनी गुंडागर्दी की नई परिभाषा लिखकर पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है।

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.

इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से
प्रधान संपादक

साप्ताहिक समय माया

प्रेसकर्मी और पत्रकार भी हैं शोषण के शिकार

श्रम विभाग के अफसरों की पोल खुली

वेज बोर्ड के सामने जब एक पत्रकार ने बताया कि श्रम विभाग के किसी अफसर की औकात नहीं है कि वे किसी अखबार के दफ्तर में जाकर वहां कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान और सुविधाओं की जानकारी हासिल कर सकें। इस पर बोर्ड के सदस्य श्री साहनी ने श्रम विभाग के अफसरों से पूछा कि ये क्या बोल रहे हैं? इस पर एक महिला अफसर ने बताया कि वह जब यहां कार्यरत थी तो अखबारों के दफ्तर में जाया करती थीं। इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी दैनिक भास्कर में हुआ करती थी। जैसे वे वहां पहुंचती थीं, तो अखबार के महाप्रबंधक या संपादक गायब हो जाया करते थे। वे मिलना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने तर्क दिया कि यह कहना गलत है कि हमारे अफसर वहां नहीं जाते। इस पर पत्रकार ने कहा कि आप जो बात बता रही हैं, वह दस साल पहले की है। अभी बताएं, कौन से अधिकारी का साहस है किसी भी अखबार का दौरा करने की। इस पर श्री साहनी ने फिर से पूछताछ की। इस बार श्रम विभाग के अफसर श्री पांडे ने आरोप को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि हम अखबार के दफ्तर में जाते हैं तो वहां के कर्मचारियों से यह लिखवाकर दे दिया जाता है कि ये अंशकालिन नौकरी पर हैं। यदि ज्यादा पूछताछ करते हैं तो अखबार मालिक सरकार को लिखकर देते हैं कि अफसर हमें परेशान कर रहे हैं। इस पर अफसरों के तबादले हो जाते हैं। यह जवाब सुनकर श्री साहनी ने चुप्पी साध ली, लेकिन उन्होंने भी यह कहने का साहस नहीं दिखाया कि इस तरह से यदि श्रम विभाग डरने घबराने लगेगा तो किसी भी क्षेत्र में मजदूरों के शोषण और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? अखबार मालिक की तरह ही फार्मस्यूटिकल कंपनियां, दाल मिलें, सीमेंट फैक्टरियां जैसे तमाम लोग सरकार से शिकायत करेंगे और श्रम विभाग कोई कार्रवाई ही नहीं करेगा। कुल मिलाकर पूरी बैठक सी लग रही थी, मानो श्रम विभाग, वेज बोर्ड और अखबार मालिक किसी एक हांडी में खिचड़ी पका रहे हों और शिकायतकर्ता पत्रकार केवल उनके लिए ऊर्जा (आग) का जरिया हो।

केंद्रीय और राज्यों के श्रम विभागों की भी औकात नहीं कि न्यूनतम वेतन भी दिलवा सकें प्रेस कर्मियों को

इंदौर। फरवरी 19/08 को रेसीडेंसी विश्राम गृह में केंद्र के श्रम विभाग के सचिव श्री साहनी ने पत्रकारों और प्रेसकर्मियों के वेतन के संबंध में पत्रकारों, उनकी यूनियन के सदस्यों, पदाधिकारियों के साथ सभा का आयोजन किया था। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंदौर प्रेस क्लब के नाम से चलने वाले तथाकथितों में से यहां पत्रकारों जो कि दैनिक प्रातः, दोपहर और सायंकालीन प्रकाशित होते हैं किसी का भी वहां दूर-दूर तक नामोनिशान नहीं था। इने-गिने जो छह लोग थे उसमें एक समय माया के श्री अजमेरा भी थे जो मालिक, कर्मचारी और हॉकर के रूप में दूसरे दैनिक समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकारों द्वारा बिना बताए गए थे, जिन्हें देखकर म.प्र. शासन के अधिकारी, श्रमायुक्त रजनीश वैश्य, उपायुक्त पांडे, दुबे व अन्य अधिकारी न केवल बुरी तरह चौंके व उनके चेहरे उतर गए थे। इसके विपरीत श्री अजमेरा वहां डंट गए।

जो दो बंदे थे वो समाचार पत्रों से सेवानिवृत्तियां ले चुके थे। योद्धाओं की श्रेणी में आ गए थे तीसरे श्री विजय दुबे थे जो नवभारत से निकाल दिए गए थे, तो योद्धा बन गए। चौथे श्री अतुल पाठक थे। 5वें श्री अजमेरा व एक व्यक्ति जो पत्रकार ही थे अर्थात शहर के 25 से ज्यादा दैनिकों का कोई प्रतिनिधि, नहीं था। एक सुश्री मनीषा दुबे थीं जो पूर्ण संतुष्ट थीं जो केवल सुनने ही गईं थीं, जो प्रभातकिरण से थीं।

मालिकों के कोप से बचने के लिए वहां कोई भी पत्रकार नहीं गया था। राज एक्सप्रेस दैनिक चैनल का एक एस.आर. केबल, भास्कर केबल, सहारा स्टार, जी न्यूज, ई टीवी के सारे जांबाज बनने वाले भी मांदों में छिपे थे, मालिकों के डर से।

शोषण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भास्कर, नई दुनिया, राजएक्सप्रेस, जागरण, नवभारत, हिन्दुस्तान टाइम्स, इंदौर समाचार, फ्री प्रेस, जर्नल सांयकालीन में चौथासंसार, अग्निबाण, दैनिक दोपहर, 6पीएम, लोकस्वामी, अपनी दुनिया, दैनिक सिटी ब्लास्ट, इंदौर समाचार, जहां 50 से 500 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं का भी कोई प्रतिनिधि या पत्रकार नहीं था। दैनिक समाचार पत्रों की कोई यूनियन कहीं भी नहीं है। स्वाभाविक है तो प्रतिनिधि भी नहीं है फिर सबके कर्मचारियों में दहशत थी कि जो पहुंचेगा उनकी नौकरी अगले बाद से 60 वर्षों में 6 से ज्यादा वेतन बोर्ड पत्रकारों की वेतन संबंधी सुविधाओं की व्याख्या कर चुके हैं। जिसमें पारुलेकर तो तीस वर्षों से ज्यादा पुराना हो चुके हैं। जो अंतिम तीन है जस्टिस माधावत तन मंडल, जस्टिस माणिसाना सिंह, वेतन मंडल जस्टिस नारायण कुरूप वेतन मंलड भी लागू हुए 8-10 वर्ष गुजर चुके हैं। पूरे देश में 70% से ज्यादा प्रेसकर्मियों को 1980 का जस्टिस माछावत वेतन मंडल के मानकों से वेतन नहीं मिल रहा है। तो माणिसानसिंग और नारायण कुरूप की अनुशंसा लागू होने की बात तो बहुत दूर की कोड़ी है।

भास्कर और जागरण जैसे समाचार पत्र समूह जिनके 20 से ज्यादा संस्करण हैं में एक तो 50 प्रतिशत ज्यादा पत्रकार और प्रेसकर्मियों को वर्षों बाद भी दैनिक रखा जाता है, ताकि दोनों हाथों से करोड़ों रुपए बटोरने वालों को दूसरे लाभ जो कर्मचारियों की भविष्यनिधि, अंशदान, पेंशन, बीमा, सुविधाएं, मकान किराया, महंगाई भत्ते आदि न देने पड़े। पाठकों को बता दें कि म.प्र. का श्रम विभाग भी कभी इनके परिसरों में घुसकर ये जानने का प्रयास नहीं करता कि आखिर 5-6 वेतन आयोग लागू किए जाने के बाद भी वहां की परिस्थितियां क्या हैं? क्या वहां के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी मिल रहा है, कि नहीं, वेतनमान की बात तो दूर, बेशक वनं के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत साफ उन समाचार पत्रों के दम पर अन्य लाभ लेता होता, इसके विपरीत उन्हें न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिए। साथ ही दूसरा यह कि पत्रकारों के अतिरिक्त अन्य प्रेसकर्मीयों को क्या वेतन मिल रहा है बेशक उन्हें अगर पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है, तो प्रेस चाहे वो कोई भ हो कर्मचारियों प्रेस छोड़कर जाता ही है, अर्थात प्रेस में अन्य संस्थानों की अपेक्षा अच्छा वेतन मिल रहा है। तभी कर्मचारी वहां कार्य कर रहा है, अन्यथा मौका मिलते ही हर प्रेस से कर्मचारी पलायन करते ही हैं।

भारत सरकार श्रम मंत्रालय के सचिव साहनी के सामने सेवा निवृत्त पत्रकारों ने जो शर्तें रखी थी उसमें एबीसी के सर्टीफिकेट के अनुसार वेतन दिलवाने और एबीसी का प्रतियों के चलन प्रमाण पत्र देने में आवश्यक वेतनमान लागू करने की बात कही गई थी। सैद्धांतिक रूप से तथ्यठोस है, परंतु एबीसी भी तो पैसे लेकर ही 2000 कॉपी के 20,000 का प्रमाण

उपग्रह फोड़ने के बहाने स्टार वार का प्रदर्शन

भविष्य में संचार उपग्रह ऐसे होंगे नष्ट

संचार उपग्रह नष्ट होते ही आधा युद्ध जीत लेगा अमेरिका

उपग्रहों को ही इसी प्रकार नष्ट किया जाएगा। संचार उपग्रहों की वर्तमान उपयोगिता के हिसाब से ऐसे उपग्रहों के नष्ट होते ही उस राष्ट्र की आधी से ज्यादा दूरसंचार व्यवस्थाएं स्वमेव नष्ट

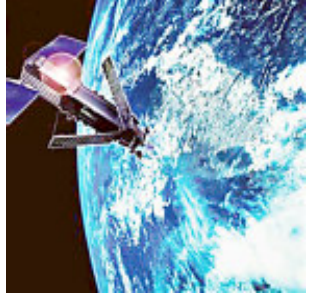

अमेरिका ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक उपग्रह जमीन से मिसाइल दाग्कर फोड़कर नष्ट किया, वास्तविकता में उस समय बाधित, व्यर्थ उपग्रह को अंतरिक्ष में फोड़ उसके टुकड़े बिखैर कर अमेरिकी रक्षा सूत्रों ने पूरी दुनिया को अपनी स्टार्स वार (उपग्रह युद्ध) की तैयारी का ही प्रदर्शन किया है। निःसंदेह इससे यूरोपीय देशों के साथ ही रूस, चीन, जैसे राष्ट्रों को जो कि एशियाई राष्ट्र है को भयाक्रांत किया है।

अमेरिका ने अंतरिक्ष में अभी अपने बेकार पड़े उपग्रह को नष्ट कर दुनिया के सामने इस बात को भी प्रदर्शन किया है कि भविष्य में वर्तमान में अधिकांश देशों के अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे संचार उपग्रहों को ही इसी प्रकार नष्ट किया जाएगा। संचार उपग्रहों की वर्तमान उपयोगिता के हिसाब से ऐसे उपग्रहों के नष्ट होते ही उस राष्ट्र की आधी से ज्यादा दूरसंचार व्यवस्थाएं स्वमेव नष्ट हो जाएगी। संचार व्यवस्थाएं नष्ट होने का सीधा अर्थ है राष्ट्र की शासकीय कार्यप्रणाली के साथ जनता की कार्य प्रणाली को आधे से ज्यादा बाधित कर युद्ध जीत जाएगा।

संचार उपग्रहों के नष्ट होने से फोन, मोबाइल, रेडियो, टीवी, ब्राडकास्टिंग, इंटरनेट, इंट्रानेट तो सीधे ही बंद या बाधित होंगे साथ ही विमानों का नेवीग्रेशन, पोजिशनिंग, लैडिंग, टेकऑफ भी बाधित होगा। दुर्घटनाग्रस्त होंगे, अर्थात वायु यातायात, व्यवस्था, जल यातायात के साथ ही उस राष्ट्र की रेल यातायात व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। बाधित होंगी, अप्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग सिस्टम, एटीएम मशीनें भी खातों की स्थिति स्पष्ट करने, धन निकालने आदि में भी बाधाएं आएंगी। अर्थात कम खर्च में शत्रु राष्ट्रों की अर्थ व्यवस्था की कमर तोड़ने उसे आंतरिक और बाह्य रूप से पंगु बनाने, बिना जवानों, सैनिकों को शेष पेज 7 पर

निवेदन

पाठकों से विनम्र निवेदन है कि भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार, अपराधों, शासकीय कर्मचारियों-अधिकारियों के निकम्मेपन, अवैध वसूली से संबंधित समाचार, क्लिप्स, दस्तावेजों की कापी, फोटोग्राफ, विडियो क्लिपिंग्स, नक्शे, जो कि साक्ष्य के रूप में समाचारों को ठोस आधार प्रदान कर सके, जो जनता व राष्ट्रहित में आवश्यक हो सीधे ही हमारे कार्यालय को डाक से, ई-मेल या अन्य माध्यमों से भेज सकते हैं। प्रेषक की सूचना पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

हमारा पता:-

समय माया

299, अम्बेडकर नगर, इन्दौर

E-mail:mwc@indiatimes.com, linkdage@hotmail.com, linkadage@indiatimes.com, Cell:9300755803-9425125569

मालिकों के कोप से बचने के लिए वहां कोई भी पत्रकार नहीं गया था। राज एक्सप्रेस दैनिक चैनल का एक वीडियो शूटर व सहायक था, अर्थात पत्रों की कोई यूनियन कहीं भी नहीं है। स्वाभाविक है तो प्रतिनिधि भी नहीं है फिर सबके कर्मचारियों में दहशत थी कि जो पहुंचेगा उनकी नौकरी अगले सुबह समाप्त है। अभी तक आजादी के

भास्कर और जागरण जैसे समाचार पत्र समूह जिनके 20 से ज्यादा संस्करण हैं में एक तो 50 प्रतिशत ज्यादा पत्रकार और प्रेसकर्मियों को वर्षों बाद भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की श्रेणी में

वेतनमान लागू करने की बात कही गई थी। सैद्धांतिक रूप से तथ्यठोस है, परंतु एबीसी भी तो पैसे लेकर ही 2000 कॉपी के 20,000 का प्रमाण पत्र देता है। शेष पेज 7 पर

नेतागिरी चमकाने, भारत में ही भारतीयों का अपमान

गैर मराठियों के विरुद्ध महाराष्ट्र में जहर

ठाकरे खानदान की राजनीति का आधार रहा है, ऐसे आंदोलन

राष्ट्र की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में पिछले कुछ महीनों से ठाकरे खानदान ने जिसमें राज ठाकरे , बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे हैं मराठी भाषियों के रहनुमा बनने, उनके वोट कबाड़ने, महाराष्ट्र में अपना वोट बैंक स्थाई करने, समर्थक इकट्ठे करने के लिए अन्य सभी भारतीयों के साथ जिसमें बिहार से लेकर गुजरात, उत्तरप्रदेश व अन्य के मूल निवासियों की जान पर बन आई है। उनके विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन, झड़पें भी मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के अन्य शहरों में हो रहे हैं।

शिवसेना के बाल ठाकरे ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत में मराठी भाषियों जो मुम्बई की फैक्ट्रियों, मिलों में काम करते थे को भी ऐसे ही इकट्ठे कर अपनी आधारशिला का शिलान्यास किया था। अब जब उनके भतीजे राज ठाकरे ने अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में समर्थक इकट्ठे करने, अपना आधार जमाने वोट बैंक बढ़ाने के लिए उसी मराठी भाषी हथियार का सहारा लेकर अपने चाचा बाल ठाकरे के इतिहास की पुनरावृत्ति ही की है।

बेशक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वर्तमान में ही विनाश का कारण बन

रही है, बसी हुई और शांत चलती मुंबई को इन नेताओं ने भारी अशांत कर रखा है। कभी बिहारियों के, कभी उत्तर भारतीयों के विरुद्ध जहर उगलकर ये भारत में ही भारतीयों का अपमान कर रहे हैं। जिस पर लोकसभा में आए दिन हंगामे हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस देश को बांटने की साजिश करार दे दिया है। परंतु राज और बाल ठाकरे इन सब तथ्यों से बेपरवाह मराठी वोट बैंक की जड़ें जमाने में लगे हैं। सबको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है, ताकि आने वाले चुनावों में ये सत्ता पर काबिज हो सकें। अगर न भी सत्ता प्राप्त कर सके तो कम से कम विधानसभा और लोकसभा में यदि एक, दो, चार सदस्य भी पहुंच पाए तो अपनी उपस्थिति का अहसास तो करवा ही पाएंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टीयां कांग्रेस उनका संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटक दलों, जिसमें लालू प्रमुख हैं के बयानों, राज ठाकरे और बाल ठाकरे के बयानों में शब्दबाण चल रहे हैं। एक दूसरे पर खुले में धमकियां दी जा रही है। प्रश्न यहां यह उठता है कि आखिर मुंबई में बसे गैर मराठियों की जिस प्रकार अपने राजनीतिक भविष्य को संवारने में निशाना बनाकर खदेड़ने, उन पर हमले करने की मुहिम चलाई जा रही है। उससे क्या महाराष्ट्र और विशेषतौर पर मुंबई का भला हो सकेगा, बेशक पहले बसी हुई मुंबई उजड़े तो फिर नवनिर्माण होगा। शायद राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहले बसी हुई मुंबई और महाराष्ट्र को जिन गैर मराठियों के दम पर बसाया गया था। पहले उनको भगाने के बहाने हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी से ध्वस्त करेंगे फिर मराठियों के दम पर 18वीं, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की मुंबई बसाकर सेना नवनिर्माण करेगी।

इसके साथ ही ज्वलंत प्रश्न यह भी है कि जिस आधुनिक मुंबई को वर्तमान में देख रहे हैं यदि उनमें मराठियों के योगदान की अगर बात करें तो शायद उनका हिस्सा 25 प्रतिशत भी नहीं होगा। मुंबई को नियोजित किया था अंग्रेजों ने जिसकी बुलंद इमारतें इंडिया गेट, व्ही.टी. स्टेशन, वृहन्न मुंबई, नगरपालिका, हर जगह उनकी इमारतों की छाप पुरानी मुंबई में है, उसमें तब भी अधिकांश गैर मराठी मजदूरों से लेकर ठेकेदारों तक ने ही अधिकांश मुंबई का निर्माण बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर अंत तक किया है, फिर गुजराती, मारवाड़ी व्यापारी अभी भी मुंबई की नब्ज हैं। उन्हें निकालने का मतलब तो आधा व्यापार तो चौपट हो ही जाएगा। बिहारी और उत्तरप्रदेशी मजदूरों को निकालने का मतलब आधी मुंबई की फैक्ट्रियों, मिलों, कार्यालयों का बंद करना पड़ेगा। कैसा है राजनीतिक रोटियां सेंकने का ये नवनिर्माण?

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित.
भोपाल प्रतिनिधि पं. एस.के. भारद्वाज, मो. 94256-37958, जबलपुर प्रतिनिधि श्री चंद्रकुमार जैन, 367, सराफा जबलपुर, इन्दौर, कार्या. फोन 4037145 मो. 9300755803, सभी विवादों की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर न्यायालय रहेगा।